एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ

सितंबर 2013
खंड XXVII अंक III

इस अंक में

6 मेना क्षेत्र में हालिया गतिविधियां
7 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
8 पिछली तिमाही
9 एक्ज़िम बैंक खबरों में
10 भारतीय सिरैमिक उद्योग : चुनौतियां एवं रणनीतियां
11 भारतीय पूंजीगत माल उद्योग : संभावनाएं
12 भारत - म्यांमार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए रोडमैप
13 एक्ज़िम बैंक के कार्यकलाप तथा साहित्य समीक्षा
14 देशों का सूक्ष्मावलोकन
15 मुद्रा की प्रवृत्तियां
16 प्रौद्योगिकी उन्मुख विनिर्माण में व्यापार संभाव्यता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

भारत का भुगतान संतुलन : संक्षिप्त विश्लेषण

भारत का भुगतान संतुलन 1966 में रूपये के अवमूल्यन, 1973 तथा 1980 में तेल संकट, 1991 के बाह्य भुगतान संकट, 1997 के पूर्व एशियाई संकट और 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट सहित कई आघातों तथा घटना-क्रमों के जोखिम तथा प्रभाव में रहा है । वैश्विक परिदृश्य में इन चुनौतियों के साथ भारत का चालू खाता घाटा (कैड) 2009-10 में जीडीपी के 2.8 प्रतिशत से लगभग दुगुना बढ़कर 2011-12 में जीडीपी का 4.2 प्रतिशत और फिर 2012-13 में जीडीपी का 4.8 प्रतिशत हो गया **(तालिका 1)** । मूल्य की दृष्टि से भारत का चालू खाता घाटा 2012-13 में 87.8 बिलियन यूएस डॉलर के उच्च स्तर पर पहुँच गया । बढ़ते चालू खाता घाटे से मुख्यतः भुगतान संतुलन प्रभावित हुआ है ।

तेल तथा उर्वरक का आयात बाजार मूल्य संकेतों के अभाव के कारण बढ़ा है, जबकि गैर-तेल आयात देशी बाजार में क्षमताओं की कमी के कारण रहा है । सोने का आयात वैकल्पिक निवेश अवसरों की कमी के कारण बढ़ रहा है, कोयला जैसे अन्य संसाधनों का आयात अनुकूल नीतियों के अभाव के कारण बढ़ा है ।

व्यापार घाटे में तेल आयात का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विनिर्मित उत्पादों के आयात ने भी व्यापार घाटे में योगदान दिया है । विनिर्मित वस्तुओं का आयात, जो 2010-11 के 140 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2012-13 में 167 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, व्यापार घाटे का लगभग 80 प्रतिशत और भारत के चालू खाता घाटे का लगभग दो गुना रहा । बढ़ता व्यापार घाटा भारत के कैड में भी प्रदर्शित हो रहा है जो 2009-10 से 2012-13 में दुगुने से अधिक हो गया ।

तालिका 1 : भारत के भुगतान संतुलन के आंकडे

भुगतान संतुलन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	**-38.4**	**-47.9**	**-78.2**	**-87.8**
जीडीपी के % के रूप में	-2.8	-2.8	-4.2	-4.8
पूंजी खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	**0.3**	**0.04**	**-0.06**	**-0.3**
वित्तीय लेखा शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	**38.2**	**50.5**	**80.7**	**85.44**

स्त्रोत : रिजर्व बैंक

भारत का पण्य व्यापार घाटा 2009-10 के 109.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2012-13 में 190.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया **(तालिका 2)** । यद्यपि वर्ष 2013-14 की पहली छमाही में आयात में 1.8 प्रतिशत संकुचन के चलते वर्ष में व्यापार घाटा कम होने की उम्मीद है, तथापि दीर्घकालिक नीति द्वारा इस मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए । बढ़ता व्यापार घाटा मुख्यतः बढ़ते स्वर्ण तथा विनिर्माण आयात के कारण है ।

देशी विनिर्माण क्षेत्र में सीमाओं के कारण भारत का निर्यात मुख्यतः निम्न मूल्य खंड में रहा है जो माँग प्रेरित तथा मूल्य संवेदी है । पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न एवं आभूषण तथा टेक्सटाइल का निर्यात 2012-13 में भारत के कुल निर्यात में संचयी रूप से 43.2 प्रतिशत रहा जो निम्न मूल्य योजन और आर्थिक मंदी के दौरान मांग संकुचन जोखिम से प्रभावित रहा हैं । अंतर्राष्ट्रीय माँग में मंदी के चलते भारत का निर्यात घटा है जबकि आयात बढ़ा है । इससे व्यापार घाटा काफी बढ़ गया है ।

देशी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की उपेक्षित स्थिति से निर्यात में मंदी आयी, जबकि उच्च लागत एवं परिष्कृत तकनीक वाले विनिर्मित उत्पादों (पूंजीगत माल, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रसायन) के आयात से व्यापार घाटा बढ़ा है । इन तीनों उत्पादों का आयात 2012-13 में 103.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा जो व्यापार घाटे का 54.5 प्रतिशत और कैड का 118 प्रतिशत रहा ।

सेवा-व्यापार में वृध्दि व्यापार घाटे की पूरी तरह से पूर्ति नहीं कर सकी **(चार्ट 1)** । सेवा-व्यापार में अधिशेष से व्यापार घाटे का लगभग 34 प्रतिशत पूरा हुआ । साफ्टवेयर निर्यात, जिसका समग्र सेवा निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा है, ने भी निर्यात वृध्दि में गिरावट दर्ज की है ।

तालिका 2 : भारत का पण्य व्यापार शेष

संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल-सप्टे)
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**178.8**	**251.1**	**306.0**	**300.4**	**152.1**
% परिवर्तन	*-3.5*	*40.5*	*21.8*	*-1.8*	*5.1^*
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**288.4**	**369.8**	**489.3**	**490.7**	**232.2**
% परिवर्तन	*-5.1*	*28.2*	*32.3*	*0.3*	*-1.8^*
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**87.1**	**106.0**	**155.0**	**164.0**	**82.9**
% परिवर्तन	*-7.0*	*21.6*	*46.2*	*5.9*	*3.6^*
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**201.2**	**263.8**	**334.3**	**326.7**	**149.4**
% परिवर्तन	*-4.2*	*31.1*	*26.7*	*-2.3*	*-4.6^*
व्यापार शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	**-109.6**	**-118.7**	**-183.3**	**-190.3**	**-80.1**

^-% परिवर्तन गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में है ।

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भुगतान संतुलन के प्रबंध और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को अक्षुण्ण रखने और उसके द्वारा घरेलू मुद्रा को स्थिर रखने के लिए चालू खाता लेन-देन में घाटे को पूंजी खाता अधिशेष से पूरा किया जाना चाहिए । 2009-10 से भुगतान संतुलन आंकड़ा आईएमएफ के बीपीएम-6 मानक पर आधारित रिजर्व बैंक के नये भुगतान संतुलन फॉर्मेट के अनुसार है । बीपीएम-6 माल तथा सेवाओं को माल के मामले में स्वामित्व के परिवर्तन और सेवाओं के मामले में उन्हें प्रदान करने के समय के सिध्दांत पर वर्गीकृत करता है । सेवा, आय तथा अंतरण को अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है, अतः 2009-10 से आंकड़े अदृश्य मदों को प्रदर्शित नहीं करते हैं । नये फॉर्मेट के अनुसार पूंजी खाता आंकड़े में निवासियों तथा अनिवासियों के बीच प्राप्त तथा देय पूंजी अंतरण और निवासियों तथा अनिवासियों के बीच गैर-उत्पादित, गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन तथा निपटान शामिल है, जबकि वित्तीय लेखा वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं से संबंधित लेन-देनों को दर्ज करता है जो निवासियों तथा गैर-निवासियों के बीच होते हैं । तथापि, दुनिया भर में और देशी अर्थव्यवस्था के भीतर मंदी के कारण पूंजी अंतर्वाह (एफडीआई तथा एफआईआई दोनों) में कमी हुई है । जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंद होती अर्थव्यवस्था के कारण भारत को कम आकर्षक पाया; अस्थिर नीतियों के कारण एफडीआई अंतर्वाह प्रभावित हुआ । वित्तीय लेखा शेष कैड की पूरी तरह से क्षतिपूर्ति नहीं कर पाया, अतः वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 दोनों में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आयी । इसका परिणाम यह रहा कि आयात कवर 2009-10 के 12 महीने की तुलना में 2012-13 में 7 महीने का रह गया **(चार्ट 2)** ।

चार्ट 1 : भारत का सेवा संतुलन

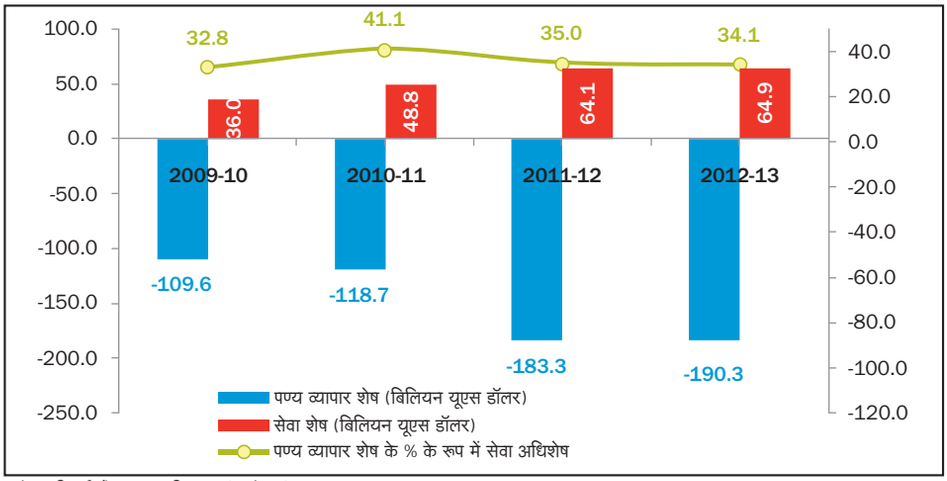

स्रोत : रिजर्व बैंक तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत का सकल विदेशी ऋण भी पिछले पांच वर्षों के दौरान बढ़ा है जो यथा 31 मार्च 2010 को 260.9 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 390 बिलियन यूएस डॉलर हो गया । कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में अल्पावधि ऋण भी इसी अवधि के दौरान 20.1 प्रतिशत से बढ़कर 24.8 प्रतिशत हो गया । विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अस्थिर पूंजी प्रवाह (संचयी पोर्टफोलियो अंतर्वाह तथा अल्पावधि ऋण - दूसरे शब्दों में हॉट मनी के लिए परिभाषित) का अनुपात भी छः महीने में सितंबर 2012 के अंत में 83.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2013 के अंत में 96.1 प्रतिशत हो गया । रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार विदेशी ऋण दायित्व, मार्च 2014 तक लगभग 172 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य के अल्पकालिक अवशेष परिपक्वता विदेशी ऋण के साथ, भारी बना रहा।

इस पृष्ठभूमि में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का तीव्र अवमूल्यन हुआ **(चार्ट 3)** । तथापि, यह कहने के लिए विश्लेषण हैं कि रुपया अपने फंडामेंटल की तुलना में धारणाओं पर अधिक प्रतिक्रियाशील रहा । वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (रीर) के साथ रुपया-डॉलर उतार-चढ़ाव रुपये के वास्तविक मूल्य पर कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा । रीर महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार देशों में मुद्रास्फीति की दर और 36 मुद्राओं के समूह को ध्यान में रखता है । इन 36 मुद्राओं में बारह ऐसे देश शामिल हैं जिनकी सामान्य मुद्रा यूरो है और इस प्रकार सूचकांक में प्रभावी रूप से 47 देशों का प्रतिनिधित्व है । यूएस डॉलर-रुपया विनिमय दरों के साथ रीर (व्यापार आधारित) की तुलना कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करती है। जहाँ वित्तीय वर्ष 2012-13 में यूएस डॉलर के मुकाबले रुपये में औसतन 11.3 प्रतिशत मूल्यह्रास हुआ, इसी अवधि के दौरान रीर (व्यापार आधारित) में मूल्यह्रास 6.7 प्रतिशत के काफी न्यून स्तर पर था । इसके आधार पर, अनुमानों से पता चलता है कि रुपया लगभग 5 प्रतिशत न्यून मूल्यांकित है ।

चार्ट 2 : भारत का निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार तथा आयात कवर

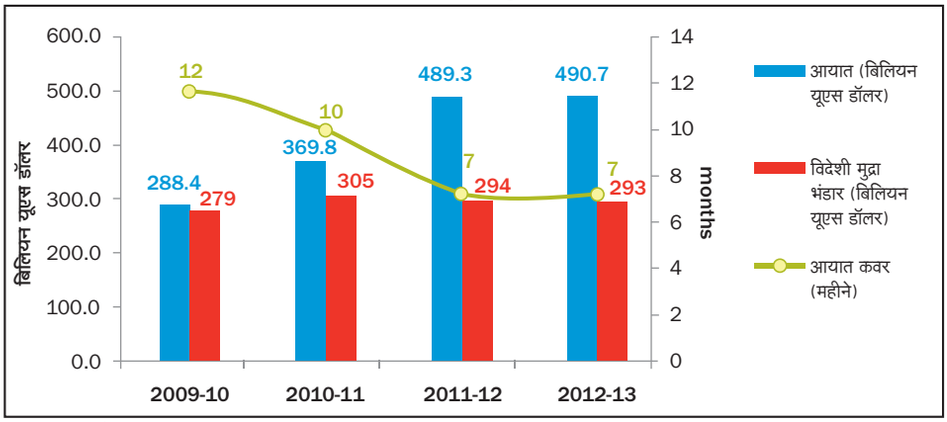

स्रोत : रिजर्व बैंक तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 3 : रुपया विनिमय दर तथा रीर उतार-चढ़ाव

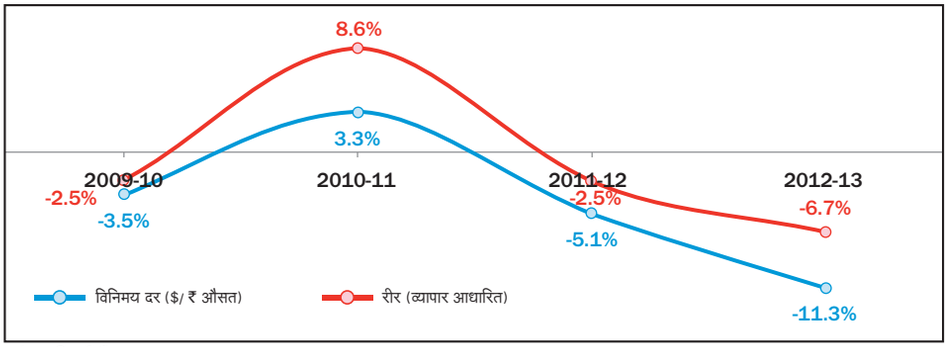

स्रोत : रिजर्व बैंक

हालांकि मुद्रा का मूल्यह्रास हमारे निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाता है, किंतु यह हमारे आयात बिल को भी अत्यधिक प्रभावित करता है और इस प्रकार स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को उत्प्रेरित करता है । निर्यातक इस आशा में अपनी निर्यात आय को रुपये में बदलने से बचते हैं कि यदि वे थोड़ा और इंतजार करें तो डॉलर और अधिक रुपया अर्जित करेगा । आयातक पहले की आंशिक हेजिंग की रणनीति की अपेक्षा अब पूर्ण सीमा तक हेजिंग कर रहे हैं।

आगे की राह

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मुख्यतः व्यापार घाटे को कम करने के लिए शीघ्र दूर किया जाना चाहिए ।

अल्पकालिक विकल्प : सरकार को चुनिंदा देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं के माध्यम से व्यापार लेन-देन का निपटान करने पर विचार करना चाहिए । सरकार को बाजार विश्वास को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा देशों के साथ मुद्रा स्वैप व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए ।

अन्य मुख्य तत्व उर्वरक (यूरिया) तथा पेट्रो उत्पादों का आर्थिक मूल्य-निर्धारण हो सकता है जो उनके कार्यक्षम उपयोग को प्रोत्साहित करेगा तथा विदेशी मुद्रा की बचत करेगा ।

दीर्घकालिक विकल्प : उपर्युक्त उपाय अल्पकालिक हैं और दीर्घकालीन कार्रवाई के लिए सिर्फ मोहलत देते हैं। इन्हें विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु देशी अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने के लिए एक समर्थकारी वातावरण उत्पन्न करने की दिशा में अनुकूलित किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आये । कुछ सुझाव हैं :

- केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से ग्रीनफील्ड एफडीआई को आकर्षित करने वाले उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों/सेक्टर विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों की पहचान करे; और राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों के प्रावधान सहित तरजीही प्रापण नीति लागू करे ।
- 'ग्रीन चैनल' एकल स्रोत अनुमोदन व्यवस्था की स्थापना जो ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनुमोदन सहित (कारोबार सूचकांक, जिसमें भारत को अपेक्षाकृत कम अंक मिलता है, हेतु मानदंड को ध्यान में रखते हुए) ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी / विनिर्माण क्षेत्रों में पूर्व-अधिसूचित अनुमोदन सहित अन्य अनुमोदन प्रदान करे ।
- ऐसे क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान।
- एमएसएमई के लिए संयंत्र एवं मशीनरी पर मौजूदा उच्चतम सीमा में वृध्दि की जानी चाहिए ताकि वे प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा गुणवत्ता अनुपालन के माध्यम से मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ सकें ।
- भारतीय फर्मों को आर एंड डी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो उन्हें प्रौद्योगिकीय रूप से मजबूत स्थिति में रखेगा । कनाडा की तरह भारत भी दोहरी कर जमा छूट प्रणाली प्रदान करने पर विचार करे जिससे आर एंड डी में वृध्दिशील व्यय और आर एंड डी में व्यय के स्तर दोनों को फायदा पहुँचता हैं । आर एंड डी कार्यकलापों में लगी एमएसएमई इकाइयों के लिए अतिरिक्त कर जमा पर भी विचार किया जा सकता है ।
- ब्राजील द्वारा (बीएनडीईएस के जरिए) प्रदान की गई रियायती वित्तपोषण सहायता की तरह भारत भी स्थानीय रूप से उत्पादित पूंजीगत माल की सोर्सिंग को प्रोत्साहित करने पर विचार करे ।
- चीन तथा कोरिया सरकार द्वारा स्थापित शिपिंग फंड के अनुरूप भारत भी एक शिपिंग फंड स्थापित करने पर विचार करे और देशी शिपायार्डों से जहाजों की प्राप्ति को प्रोत्साहित करे ।
- विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों में सहायता के लिए विशेष मध्यावधि पुनर्वित्त स्त्रोत यथा टीयूएफएस जैसी योजना घोषित की जानी चाहिए ।

कारोबार अवसर तथा प्राप्त संविधाएं

यथा सितंबर 2013 को नई परियोजनाएं

देश/निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी से ऋण
दि पॉवर होल्डिंग कंपनी ऑफ नाइजीरिया पीएलसी. परियोजना प्रबंध इकाई 7, हामबोरी स्ट्रीट वुज़ 2 अबुजा 900288 नाइजीरिया **संपर्क :** इंजी. ए. जे. सिरोमा महाप्रबंधक टेली. : +234-9-8705449, 8746421 ईमेल : phcnpmu@nepapmu.org.ng	**बिजली तथा गैस सुधार परियोजना - अतिरिक्त वित्तपोषण** परियोजना के कार्य में 330/132 केवी तथा 132/33 केवी ट्रान्समिशन उप-स्टेशन का निर्माण, पुनरूत्थान तथा पुनः प्रवर्तन शामिल है ।	**विश्व बैंक** 200 मिलियन यूएस डॉलर
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हेतु कार्यपालक सचिवालय बोलवार्ड डु 1 ई आर नवम्ब्रे बिल्डिंग 'लॉरी डु गोल्फ', पहली मंजिल बीपी 3385 बुजुम्बुरा ।। बुरून्दी **संपर्क :** श्री पाइरे नदमामा कार्यपालक सचिव टेली. : +257-2225 8750 ईमेल : pierre.ndamama@setic.gov.bi	**क्षेत्रीय संचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम (आरसीआईपी-2)** आरसीआईपी विश्व बैंक समूह का एक क्षेत्रीय लिखत है जिसका उद्देश्य पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तिजी क्षेत्र के निवेश को उत्प्रेरित करना है । परियोजना में बुरून्दी संचार प्रणाली के लिए नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर तथा संबंधित साफ्टवेयरों की आपूर्ति, स्थापना, विन्यास तथा कमीशनिंग शामिल है ।	**विश्व बैंक** 81.5 मिलियन यूएस डॉलर
मैकडोनियन रेलवेज़ ट्रान्सपोर्ट जेएससी III मैकडोनस्का ब्रिगेड नं. 66 1000 स्कॉपजे मैकडोनिया गणराज्य **संपर्क :** श्री किरे डिमानोस्की टेली. : +389 23248701 फैक्स : +389 23248719 ईमेल : kiredimanoski@mztransportad.com.mk	**मैकडोनियन रेलवेज़ फ्लीट नवीकरण परियोजना** परियोजना में 4 नये डीजल पैसेंजर बहुविध यूनिटों (डीएमयू) तथा 2 नये इलेक्ट्रिक बहुविध यूनिटो (ईएमयू) की डिज़ाइन, विनिर्माण, आपूर्ति तथा कमीशनिंग शामिल है ।	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** 59 मिलियन यूरो
ऊर्जा विकास एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय नेमनजीना 11 स्ट्रीट सर्बिया गणराज्य **संपर्क :** सुश्री अग्निजका कोजलोवस्का टेली. : +44 20 7338 7488 फैक्स : +44 20 7338 7451 ईमेल : kozlowsa@ebrd.com	**सर्बिया में ऊर्जा अधिनियम की परामर्शी सेवा समीक्षा** इस कार्य को हाल में लेने के लिए चुने गए परामर्शदाता से निम्न कार्य अपेक्षित हैं : सर्बिया में नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रक्रिया की अनुमति देने में संभावित अड़चनों की पहचान करना, इस प्रक्रिया को सुधारने के लिए संशोधन तथा विकल्प प्रस्तावित करना, इस ऊर्जा अनुमति प्रक्रिया के सुधार हेतु प्रस्ताव विकसित करना और नवीकरण ऊर्जा अनुमति के लिए सर्व सेवा केन्द्र संकल्पना विकसित करने के साथ सहायता प्रदान करना शामिल है ।	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** 0.2 मिलियन यूरो
सिलोन विद्युत बोर्ड सर चित्तमपालम ए गार्डीनर मवाथे 3 री मंजील, गोबा बिल्डिंग कोलम्बो, श्रीलंका **संपर्क :** परियोजना प्रबंधक टेली. : +94 112 448 749 फैक्स : +94 112 448 749 ईमेल : pmceneip2@ceb.lk	**स्वच्छ ऊर्जा तथा नेटवर्क कार्यकुशलता सुधार परियोजना** परियोजना में पैकेज 2 के लिए संयंत्र की खरीद, डिज़ाइन, आपूर्ति तथा स्थापना ; 132 केवी ट्रान्समिशन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉट-ए का निर्माण : 15 एमवीए (3 x 5 एमवीएआर), 33 केवी पर कैपासिटर बैंक के साथ केगालें में नये ग्रिड उप-स्टेशन का निर्माण तथा थुलहिरिया में मौजूदा 132 x 33 केवी ग्रिड उप-स्टेशन का प्रवर्धन शामिल है ।	**एशियाई विकास बैंक** 130.9 मिलियन यूएस डॉलर

देश/निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी से ऋण
दि अफगानिस्तान ब्रेश्ना शेरकत (डीएबीएस), मुख्यालय चमन होजौरी, काबुल अफगानिस्तान **संपर्क :** डॉ. वहीदुल्ला पोपलजाई निदेशक - पीएमओ टेली. : +0093 0 700279767 ईमेल : waheedullah.popalzai@pmo.dabs.af	**बदकहान तथा बेमयान प्रांतो में लघु हाइड्रोपॉवर संयंत्रों का विकास** इन्टेक, वियर, हेडरेस केनाल, फोरबे, पेनस्टॉक, पॉवरहाउस, स्टील वर्क जैसी सिविल संरचनाओं सहित 500 केवी प्रत्येक क्षमता के बहारक (लॉट 1) तथा टॉपची (लॉट 2) लघु हाइड्रोपॉवर संयंत्रों का निर्माण तथा कार्य के प्रापण के रूप में विद्युत-यांत्रिक उपकरण की आपूर्ति तथा स्थापना और परीक्षण तथा कमीशनिंग ।	**एशियाई विकास बैंक** 700 मिलियन यूएस डॉलर
दि तंजानिया नेशनल रोड एजेंसी (टैनरोड्स) मुख्यालय टेंडर बोर्ड, 4 थी मंजिल एयरटेल हाऊस, अली हसन मविनिल/कवावा रोड जंक्शन पो.बा. 11364, दारे-सलाम तंजानिया **संपर्क :** सचिव टेली. : +255 222926001/6	**सड़क क्षेत्र सहायता परियोजना - I** परियोजना में नामतुम्बो-टुंडुरू सड़क का उनयन शामिल है । सड़क को नीचे दर्शाए रूप में तीन लॉटों में विभाजित किया गया है : लॉट ए : नामतुम्बो - किलीमसेरा 60.7 किमी. लॉट बी : किलीमसेरा - मेटमंगा 68.2 किमी. लॉट सी : मेटमंगा - टुंडुरू 58.7 किमी.	**अफ्रीकी विकास बैंक** 45 मिलियन यूएस डॉलर
ईस्ट डेल्टा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी शेबिन इल कॉम स्ट्रीट अरैशिया मिसर इस्मालिया ईजिप्ट **संपर्क :** प्रापण क्षेत्र प्रमुख टेली. : +20 64 3371906 फैक्स : +20 64 3376285 ईमेल : procurementsector_EDEPC@hotmail.com	**स्यूज थर्मल पॉवर प्लांट** कार्य में स्यूज थर्मल पॉवर संयंत्र के लिए यांत्रिक उपकरणों/पाइप स्थापनाओं के लिए डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेशन, फर्नीशिंग, स्थल पर सुपुर्दगी, भंडारण, स्थापना, प्रशिक्षण, परीक्षण, कमीशनिंग, परिचालन में लाना; तथा परिचालनात्मक स्वीकृति प्रमाणपत्र (ओएसी) तक सभी उपकरणों तथा प्रणालियों का रखरखाव, तकनीकी दस्तावेज तथा निर्माण दस्तावेज तैयार करना शामिल है ।	**अफ्रीकी विकास बैंक** 550 मिलियन यूएस डॉलर

भारतीय कंपनियों/परामर्शदाताओं द्वारा प्राप्त चुनिंदा संविदाएं

डीईएसएल इंडिया, नई दिल्ली	**विश्व बैंक** से सहायता प्राप्त - उलानबातर जिले के लिए संभाव्यता अध्ययन तैयार करने के लिए संविदा ।
सिप्ला लि., मुंबई	**विश्व बैंक** से सहायता प्राप्त - ईथियोपिया की पोषण परियोजना के लिए औषधियों की आपूर्ति हेतु संविदा ।
केईसी इंटरनेशनल लि., मुंबई	**विश्व बैंक** समूह से सहायता प्राप्त - तंजानिया की बैकबोन ट्रान्समिशन निवेश परियोजना के लिए संयंत्र एवं उपकरण-लॉट 3 : सिंगिदा - शिन्यांगा की आपूर्ति, स्थापना तथा कमीशनिंग हेतु संविदा, जिसमें 228 किमी. लम्बी 440 केवी ओवरहेड ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण शामिल है ।
ज्योति स्ट्रक्चर्स लि., मुंबई	**विश्व बैंक** समूह से सहायता प्राप्त - तंजानिया की बैकबोन ट्रान्समिशन निवेश परियोजना के लिए संयंत्र एवं उपकरण-लॉट 2 : डोडोमा - सिंगिदा की आपूर्ति, स्थापना तथा कमीशनिंग जिसमें 217 किमी. लम्बी 400 केवी ओवरहेड ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण शामिल है ।
ओसॉ एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि., अम्बाला	**विश्व बैंक** समूह से सहायता प्राप्त - ट्यूनिशिया में रणनीतिक पण्यों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान में सहायता तथा कृषि उपकरणों के प्रापण हेतु संविदा ।
दि इंड्योर प्रा.लि., नई दिल्ली	**विश्व बैंक** समूह से सहायता प्राप्त - जिम्बाब्वे की आपात विद्युत पुनरूत्थान परियोजना (ईपीआईआरपी) के लिए हवांगे थर्मल पॉवर स्टेशन के ऐश प्लांट के उन्नयन तथा पुनरूत्थान हेतु संविदा ।

6 मेना क्षेत्र में हालिया गतिविधियां

2011 में मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका को हिला देने वाली क्रांति का असर क्षेत्र के आर्थिक कार्य-निष्पादन और राजनितिक अस्थिरता पर बरकरार है । 2011 की अरब क्रांति (स्प्रिंग) ने समूचे मेना क्षेत्र को प्रभावित किया । उत्तर अफ्रीका में सबसे अधिक विद्रोह ट्यूनिशिया, मिस्र तथा लीबिया में देखा गया क्योंकि इन सभी देशों में व्यवस्थागत परिवर्तन हुए और लम्बे समय में संगठित निष्पक्ष चुनाव हुए ।

व्यापक प्रतिरोध के चलते कई सरकारों को जनता की माँगो को पूरा करने के लिए सामाजिक खर्च को बढ़ाने और प्रतिरोधों को उपद्रवों मे बदलने से रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा । क्रांति और बाद में आर्थिक अव्यवस्था के फलस्वरुप राजस्व में गिरावट के साथ लोक ऋण बढ़ा है । मध्य पूर्व में कई देशों ने प्रदर्शनकरियों को खुश करने के लिए सामाजिक व्यय कार्यक्रम शुरु किया है। इससे राजकोषीय संतुलन पर गंभीर दबाव पड़ा है । सऊदी अरब जैसे संपन्न देशों के मामले में भी यही लागू है जिसने 2013 में अपने राजकोषीय संतुलन पर दबाव देखा क्योंकि, इस दौरान वादा किये गये सामाजिक तथा विकास व्यय का कार्यान्वयन शुरु हुआ । कतर तथा ओमान ने छोटे कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है जिससे राजकोषीय संतुलन पर अधिक दबाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

मेना में राजनीतिक अस्थिरताओं से क्षेत्र की अल्पकालीन आर्थिक संभावनाओं का प्रभावित होना जारी है । आईएमएफ के अनुसार क्षेत्र के तेल निर्यातकों अर्थात अल्जीरिया, बहरीन, ईरान, ईराक, कुवैत, लीबिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई तथा यमन में अच्छी वृध्दि दरें (2012 में औसतन 5.7 प्रतिशत) के कम होकर 2013 में 3.2 प्रतिशत हो जानें का अनुमान है। यह मुख्यतः सामान्य वैश्विक मांग के बीच तेल उत्पादन को कम करने के कारण है। अधिकांश मेना तेल आयातकों में अर्थिक स्थितियां कमजोर बनी हुई हैं । क्षेत्र के तेल आयातकों, जिनमें जिबूती, मिस्र, जॉर्डन, लेबनॉन, मौरीटेनिया, मोरक्को, सूडान तथा ट्यूनिशिया शामिल है, में वृद्धि दर 2013 में 3 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर रहने की संभावना है । कई तेल आयातकों के अंतराष्ट्रीय भंडार पर चुनौतीपूर्ण बाह्य आर्थिक वातावरण का दबाव बना हुआ है । वे तेल आयातक जो विशेषकर राजनीतिक उथल-पुथल से उबर पाए । बढ़ते जोखिम प्रीमियम, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और राजकोषीय तथा चालू खाता घाटे के वित्तपोषण में बढ़ती कठिनाई के चलते नाजुक स्थिति में हैं ।

हालांकि मिस्र में सरकार में हाल के बदलाव पर फोकस रहा है, मिस्र, ट्यूनिशिया, लेबनान, जॉर्डन तथा ईरान सहित मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका क्षेत्र में पांच देश मंदी, बढ़ते राजकोषीय घाटे और ऋण, उच्च बेरोजगारी तथा मुद्रास्थिति से जूझ रहे हैं । मिस्र में लगातार राजनितिक उथल-पुथल और सीरिया जॉर्डन तथा लेबनान में गृह युध्द उनकी आर्थिक स्थिति को बदतर बनाने की आशंका को जन्म देते हैं, लीबिया में राजनीतिक स्थिरता बहुत दूर की बात है। लीबिया में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते तेल अपूर्ति में व्यवधान के डर से कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई । अल्जरिया तथा मोरक्को में लगातार अशांति का भी क्षेत्र पर प्रभाव रहा है। सामान्य रुप में, इससे पूरे क्षेत्र में विदेशी निवेशकों का विश्वास कम हुआ है, तथा पर्यटन प्रभावित हुआ है जिससे विशेषकर पड़ोसी लेबनान तथा जॉर्डन की छोटी अर्थव्यवस्थाएं अत्याधिक प्रभावित हुई । सीरिया लेबनान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और लेबनान भी दोनों देशों के लिए आयात तथा निर्यात के परिवहन के लिए मार्गस्थ देश के रुप में कार्य करता है । लेबनानी राजनीति सीरिया में हस्तक्षेप पर पूरी तरह से विभाजित है और सरकार को गिरने से बचाने के लिए कोई रुख लेने से कतराने की संभावना है । इस्राइल में, सामाजिक आर्थिक सुधारों पर असंतोष के चलते सामाजिक अशांति बनी हुई है । ट्यूनिशिया में आर्थिक सुधारों ने 2013 की पहली तिमाही में अपनी गति खो दी क्योंकि एफडीआई अंतर्वाह और पर्यटन प्राप्तियां फरवरी में एक राजनितिक हस्ती की हत्या के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण पुनः प्रभावित हुँई । 2013 के पहले दो महीनों के दौरान 2012 की इसी अवधि की तुलना में कुल एफडीआई में 9 प्रतिशत की गिरावट आयी । ईरान में, 2012 में वृद्धि 2 प्रतिशत संकुचित हुई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण तेल के उत्पादन में तीव्र गिरावट आयी ।

नेमा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां 2014 मे क्रमिक सुधार की संभावनाओं के साथ 2013 में मंद रहेंगी ।

मेना क्षेत्र में एक्ज़िम बैंक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) मेना क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए व्यापक वित्तपोषण, सलाहकारी तथा सहायता कार्यक्रम चलाता है । मेना क्षेत्र में भारतीय उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए एक्ज़िम बैंक ने मेना क्षेत्र में निम्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा कई संयुक्त उद्यमों की सहायता की है इनमें शिपिंग (ट्रान्सफ्रेट शिपिंग सर्विसेस), हेल्थकेअर (कोर हेल्थकेयर लि.), सीमेंट (जे.के. सीमेंट), इस्पात (एस्सार स्टील), एल्यूमिनियम (रैक एल्यूमिनियम) इत्यादि प्रमुख है ।

31 मार्च 2013 को मेना क्षेत्र में एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कुल चालू परियोजनाएं ₹ 62.057 करोड़ मूल्य की थीं। इसमें कतार, लीबिया, यूएई तथा ओमान में परियोजनाएं शामिल हैं । लगभग 38 प्रतिशत परियोजनाएं (प्राप्त परियोजनाओं के मूल्य के अनुसार) इसी क्षेत्र से हैं ।

मेना क्षेत्र में भारत से परियोजना निर्यात का क्षेत्रवार तथा सेक्टरवार विश्लेषण (₹ करोड़)

क्षेत्र	इंजी. एवं निर्माण	बिजली (उत्पादन एवं पारेषण)	तेल एवं गैस	इंफ्रास्ट्रक्चर	परामर्शी	अन्य	कुल योग
मध्यम पूर्व	21,609	12,955	8,864	495	-	1,064	44,987
उत्तर अफ्रीका	3,765	2,099	5,266	5,571	369	-	17,070

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्यमों पर विशेष बल देते हुए प्रभावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रुप में ऋण-व्यवस्थाएं (एनओसी) देने पर विशेष जोर दिया है । एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, सॉवरिन सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित ऋण शर्तो पर विकासपर और बुनियादी संरचना, परियोजनाएं, उपकरण, माल, सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं । साथ ही भारतीय निर्यातक शिपिंग दस्तावेजों के आधार पर एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य का भुगतान दायित्व रहित आधार पर प्राप्त कर सकते हैं । एक्ज़िम बैंक स्वयं के अलावा भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण व्यवस्थाएं प्रदान करता है । ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल की शिपिंग पर भारतीय निर्यातकों को संविदा मूल्य की प्रतिपूर्ति अपफ्रंट करता है, बशर्तेकि माल एवं सेवाओं के कुल संविदा मूल्य का कम से कम 75 प्रतिशत भारत से लिया जाए । एक्ज़िम बैंक की ऋण व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों के लिए जोखिम-मुक्त, दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का बेहतरीन विकल्प हैं ।

एक्ज़िम बैंक की वर्तमान मे 178 ऋण व्यवस्थाएं परिचालनरत हैं, जिनके अंतर्गत अफ्रीका , एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया तथा सीआईएस के 75 देशों को शामिल करते हुए 9.54 बिलियन यूएस डॉलर की राशि अलग-अलग क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के निर्यात वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है । इन ऋण व्यवस्थाओं ने अलग-अलग क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के निर्यात को बढ़ावा दिया है । जिनमें कृषि, परिवहन, संचार, विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल है । भारतीय परियोजना निर्यात वित्तपोषण के लिए प्रदान की जा रही है ये ऋण व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देशों में विकास के साथ-साथ भारतीय विशेषज्ञता एवं परियोजना निष्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं ।

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश और सहयोग से जुलाई-सितंबर 2013 के दौरान निम्नलिखित चार ऋण व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किये हैं :

- नाइजर में 30 गाँवों के विद्युतीकरण तथा 5 मेगावॉट की सौर फोटो वोल्टीय प्रणाली की स्थापना के लिए नाइजर सरकार को 35.54 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई । भारत सरकार के आदेश पर नाइजर सरकार को प्रदान की गई यह तीसरी ऋण व्यवस्था है । सभी ऋण व्यवस्थाओं का कुल मूल्य 71.54 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है।

- लाईबेरिया गणराज्य सरकार को बिजली उत्पादन परियोजना के लिए 144 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण व्यवस्था ।

- लाओ पीडीआर सरकार को चार प्रमुख प्रांतों में बाँध के निर्माण और सिंचाई प्रणालियों के विकास के लिए 30.94 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण व्यवस्था । यह लाओ पीडीआर सरकार को प्रदान की जा रही चौथी ऋण-व्यवस्था है जिसे मिलाकर कुल ऋण व्यवस्थाओं की राशि 153.83 मिलियन यूएस डॉलर हो गयी है ।

- बेनिन में 69 गांवों में जल आपूर्ति योजनाओं के उन्नयन के लिए बेनिन सरकार को 42.61 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण व्यवस्था । भारत सरकार के आदेश पर बेनिन को एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की गई यह तीसरी ऋण व्यवस्था है इसे मिलाकर ऋण व्यवस्थाओं की कुल राशि 72.61 मिलियन यूएस डॉलर हो गयी है ।

- सूडान सरकार को 125 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण व्यवस्था । यह चीनी परियोजना के वित्तपोषण के लिए 150 मिलियन यूएस डॉलर की कुल ऋण वचनबध्दता की दूसरी तथा अंतिम किस्त है । इसे मिलाकर सूडान को सात ऋण व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं । इनके अंतर्गत कुल राशि 691.90 मिलियन यूएस डॉलर है ।

- निकारगुआ में दो विद्युत उप-स्टेशनों के निर्माण के लिए भारत से उपकरणों के वित्तपोषण के लिए निकारगुआ सरकार को 10 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण व्यवस्था ।

- वियतनाम में दो परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वियतनाम समाजवादी गणराज्य सरकार को 19.50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था । उपर्युक्त एलओसी करार पर हस्ताक्षर करने के साथ एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार के आदेश पर वियतनाम को प्रदान की गई तीनों ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत कुल राशि 91.50 मिलियन यूएस डॉलर हो गई है ।

- मोज़ाम्बिक सरकार को ग्रामीण पेय जल परियोजना के विस्तार के लिए 19.72 मिलियन यूएस डॉलर, मोज़ाम्बिक मे टिका, बुजी तथा नोंवा सोफाला के बीच सड़क के पुनरुत्थान के लिए 149.72 मिलियन यूएस डॉलर और मोज़ाम्बिक में 1200 मकानों के निर्माण के लिए 47 मिलियन यूएस डॉलर की तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई है । कुल 216.44 मिलियन यूएस डॉलर राशि की उपर्युक्त तीन एलओसी करारों पर हस्ताक्षर किये जाने के साथ, एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार के आदेश पर मोज़ाम्बिक को प्रदान की गई 12 ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत कुल राशि 639.44 मिलियन यूएस डॉलर हो गई है ।

अधिक जानकारी के लिए
कृपया संपर्क करें

सुश्री गीता पूजारी
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड,
मुंबई - 400 005.

फोन : (022) 22162073
(022) 22172310
फैक्स : (022) 22182460
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

रिजर्व बैंक ने रेपो दर बढ़ाई

रेपो दर अर्थात् अल्पकालिक उधार दर 4 सितंबर 2013 को तत्काल प्रभाव से 7.25 प्रतिशत से 25 आधार बिन्दु बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई. तथापि रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर में 0.75 प्रतिशत की कटौती कर 9.5 प्रतिशत और नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) के दैनिक रखरखाव की सीमा को कम करके लिक्विडिटी की स्थिति को सहज बनाने की दिशा में कदम उठाये हैं.

ब्याज सहायता की दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत की गई

सरकार ने ब्याज सहायता की मौजूदा दर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. वर्तमान में, सभी क्षेत्रों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम निर्यातक, इस योजना के लाभार्थी हैं. इसके अलावा, निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित निर्यातक ब्याज सहायता पाने के लिए पात्र हैंः (i) हैंडलूम (ii) हस्तशिल्प (iii) कालीन (iv) खिलौने तथा खेल-कूद के सामान (v) प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद (vi) सिले-सिलाये वस्त्र (vii) इंजीनियरिंग क्षेत्र में 235 टैरिफ लाईनें और (viii) आईटीसी (एचएस) (टेक्सटाइल्स तथा मेड अप्स) के अध्याय 63 में 6 टैरिफ लाइनें. ब्याज सहायता की दर में वृध्दि से लघु एवं मध्यम उद्यमों के निर्यातकों और अधिकांश श्रम गहन क्षेत्रों के निर्यातकों को लाभ मिलेगा.

समान सेवा - समान प्रभार

रिजर्व बैंक ने उधारदाताओं को निदेश दिया है कि वे अपने ग्राहकों में भेदभाव न करें और एकरूप, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मूल्य-निर्धारण नीति का अनुसरण करें. बैंकों अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मूल शाखा तथा मूलेतर शाखाओं में अपने ग्राहकों के बीच भेद-भाव न करें. यदि कोई विशिष्ट सेवा मूल शाखा में निःशुल्क प्रदान की जाती है तो वह मूलेतर शाखाओं में भी उपलब्ध होनी चाहिए. ग्राहकों द्वारा मूल शाखा तथा मूलेतर शाखाओं में किये गये एक ही प्रकार के लेन-देनों के लिए परस्पर सोल प्रभार (उत्पादों एवं सेवाओं के लिए बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को लगाये जाने वाले प्रभार) के संबंध में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए.

एनबीएफसी के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट मानदंड कड़े किये गये

रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कहा है कि वे खुदरा निवेशकों से प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसा न जुटाएं. हाल ही में यह पाया गया है कि एनबीएफसी प्राइवेट प्लेसमेंट में माध्यम से विशेषकर डिबेंचरों के जरिए बड़े पैमाने पर आम जनता से संसाधन जुटा रही हैं. रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अन्य वित्तीय कंपनियों के समतुल्य ला दिया है जो पहले उन पर लागू नहीं था. विनियामक डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट को एनबीएफसी द्वारा अपफ्रंट पहचान किये गये 49 निवेशकों तक सीमित करना चाहता है. एकल निवेशक के लिए न्यूनतम अभिदान 25 लाख रूपये और उसके बाद 10 लाख रूपये के गुणकों में होगा. इसके अलावा, डिबेंचरों के जरिए जुटायी गई राशि स्वयं एनबीएफसी द्वारा ही उपयोग की जाएगी, न कि अन्य समूह या मूल फर्मों के लिए संसाधन के रूप में.

रिजर्व बैंक ने गैर-सीटीएस चेकों के चरणबध्द रूप से समापन की प्रक्रिया को सरल बनाया

शेष गैर-चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) 2010 मानक चेकों को हटाने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 31 जुलाई 2013 करने के बाद रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2014 से उत्तरदिनांकित तथा ईएमआई चेकों सहित शेष गैर-सीटीएस 2010 लिखतों के समाशोधन के लिए मुंबई, चेन्नै तथा नई दिल्ली के तीन सीटीएस केन्द्रों में अलग समाशोधन सत्र शुरू किया है. अलग समाशोधन सत्र 30 अप्रैल 2014 तक सप्ताह में तीन बार सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को रहेगा. इसके बाद 31 अक्तूबर 2014 तक सप्ताह में दो बार (सोमवार और शुक्रवार) और इसके बाद 1 नवंम्बर 2014 से सप्ताह में एक बार प्रत्येक सोमवार को कर होगा.

बैंकों को आयात ऋण अवधि को परिचालन चक्र से जोड़ना चाहिए

अल्पावधि ऋण से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे आयात हेतु व्यापार ऋण को परिचालन चक्र तथा व्यापार लेन-देन से जोड़ें. बैंकरों का मानना है कि यह निदेश ऋण उपयोग पैटर्न को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में एक कदम है. व्यापार ऋण के लिए सस्ती दरों के चलते इकाई के परिचालन चक्र से अधिक अवधि के लिए उधार लेने की प्रवृत्ति पनप रही थी. उदाहरण के लिए, यदि इकाइयों का परिचालन चक्र (माल तथा सामग्री आयात करना) तीन महीने है तो वे विदेशी मुद्रा में सस्ती निधियों का फायदा उठाने के लिए छः महीने का व्यापार ऋण मांगती हैं. किन्तु हेजिंग न करने पर इकाइयां विदेशी मुद्रा जोखिम में पड़ जाती थीं.

रिजर्व बैंक ने पूर्ण महिला बैंक के लिए सिध्दांत रूप में मंजूरी दी

रिजर्व बैंक ने भारत की पहली पूर्ण महिला बैंक की स्थापना के लिए सिध्दांत रूप में मंजूरी दे दी है. प्रस्तावित बैंक केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित पहला वाणिज्यिक बैंक होगा और प्रारंभ में छः शाखाओं के साथ इसकी समग्र भारत में उपस्थिति होगी. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में प्रस्तावित है. सरकार बैंक की प्रदत्त पूंजी में प्रारंभ में 1000 करोड़ रूपये निवेश करेगी. बैंक महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने के अलावा मुख्यतः महिलाओं और महिला-संचालित कारोबार को ऋण देगा. इसमें मुख्यतः महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा और यह महिलाओं तथा पुरूषों दोनों से जमाराशियां स्वीकार करेगा.

एक्ज़िम बैंक की आंध्र प्रदेश में ग्रासरूट संगठनों को सहायता

एक्ज़िम बैंक ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में आधारित ग्रामीण ग्रासरूट स्वैच्छिक संगठन 'कला सृष्टि' को वित्तीय सहायता प्रदान की है. कला सृष्टि विभिन्न पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों जैसे लकड़ी की नक्काशी, कलमकारी पेंटिंग और वुडेन लैकर वेयर का उत्पादन कर रही है. एक्ज़िम बैंक ने अपनी ग्रासरूट पहल के अंतर्गत कला सृष्टि को सहायता प्रदान की है. इस पहल का उद्देश्य निर्यात संभाव्यता वाले ग्रामीण उद्यमों / प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करना है. इस पहल का अंतर्निहित उद्देश्य देश भर में शिल्पकारों / उत्पादक समूहों / क्लस्टरों / लघु उद्यमों / एनजीओ की सहायता कर उनकी इकाइयों से निर्यात को प्रोत्साहित करके उनके उत्पादों के लिए लाभप्रद प्रतिफल प्राप्त कराना है. कला सृष्टि को बैंक की सहायता मुख्यतः उसके परिचालनों को बढ़ाने और संगठन के पारंपरिक शिल्पकारों के विशाल वर्ग तक उसकी पहुंच बढ़ाने में सहायता करने की दिशा में एक कदम है. इस कार्यक्रम से कला सृष्टि से जुड़े लगभग 5000 शिल्पकारों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है जो लकड़ी की नक्काशी, कलमकारी पेंटिंग और वुडेन लैकर वेयर जैसी हस्तशिल्प मदों के उत्पादन में लगे हैं. एक्ज़िम बैंक की सहायता से शिल्पकारों द्वारा वर्तमान में तैयार किये जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ सकती है और इस प्रकार न केवल घरेलू बाजार में उनकी बिक्री बढ़ेगी, बल्कि विदेशों में भी बाजार बढ़ाने में उन्हें सहायता मिलेगी.

ईडरा अवॉर्ड 2012 के विजेता की घोषणा

डॉ. हरेन्द्र कुमार बेहरा को उनके शोध प्रबंध 'दि इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशिल ओपननेस : ऐन एसेसमेंट ऑफ दि इंडियन इंटरप्राइज़ेज़' के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास अनुसंधान वार्षिक (ईडरा) अवॉर्ड 2012 का विजेता घोषित किया गया है. मुख्य अतिथि डॉ. रघुराम राजन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा यह अवॉर्ड प्रदान किया गया. इस अवॉर्ड में दो लाख पचास हजार रुपये की राशि तथा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है. 1989 में शुरू किया गया एक्ज़िम बैंक का ईडरा अवॉर्ड भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालयों से भारतीय नागरिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास तथा संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध प्रबंध के लिए दिया जाता है. वर्ष 2012 अवॉर्ड का चौबीसवां वर्ष था. पुरस्कृत शोध प्रबंध पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री रंगनाथन ने रेखांकित किया कि अनुसंधान अध्ययन वित्तीय भूमंडलीकरण के विभिन्न मूलभूत पहलुओं पर और विशेषकर विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष हालिया संकट तथा मंदी के संदर्भ में प्रकाश डालता है.

वुमन ऑन विंग्स के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर

एक्ज़िम बैंक ने वुमन ऑन विंग्स, जो आस्टरलिट्ज़, नीदरलैंड आधारित एक अलाभकारी संगठन है और वर्ष 2018 तक ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए एक मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए भारत में सामाजिक उद्यमों के साथ कार्य कर रही है, के साथ एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किये. एमओसी का उद्देश्य सहयोग के क्षेत्रों तथा साधनों की पहचान करना है जिनके माध्यम से भारतीय ग्रासरूट / सामाजिक उद्यमों की सहायता की जा सके जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ा सकें. एमओसी के अंतर्गत, एक्ज़िम बैंक तथा वुमन ऑन विंग्स दोनों अपने ज्ञान का आदान-प्रदान करेंगे और उदीयमान सामाजिक उद्यमों को वित्तीय तथा सलाहकारी सेवा सहित अतिरिक्त सहायता के लिए एक-दूसरे को जोड़ेंगे. एक्ज़िम बैंक ग्रामीण ग्रासरूट कारोबारी उद्यमों को वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण तथा निर्यात विपणन से संबंधित सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदानकर उनके उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है. इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत से रोजगार के स्थायी अवसर और निर्यात को बढ़ावा देना है. एक्ज़िम बैंक ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई ग्रासरूट संगठनों / उद्यमों को सहायता प्रदान की है.

एक्ज़िम बैंक ने म्यांमार में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला

यांगोन के माननीय मुख्य मंत्री यू मिंट स्वे और म्यांमार में भारत के राजदूत माननीय श्री गौतम मुखोपाध्याय की गौरवमयी उपस्थिति में 9 सितंबर 2013 को यांगोन में एक्ज़िम बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर भारत तथा म्यांमार के बीच व्यापार तथा निवेश अवसर पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया जिसमें म्यांमार के उच्च पदाधिकारियों, राजनयिकों, बहु-पक्षीय एजेंसियों, बैंकों, बड़ी संख्या में कंपनियों और भारतीय डायस्पोरा ने भाग लिया. म्यांमार में भारत के राजदूत श्री गौतम मुखोपाध्याय ने यांगोन में कार्यालय खोलने के एक्ज़िम बैंक के निर्णय का स्वागत किया जो इसका आठवां विदेशी क्षेत्रीय कार्यालय होगा. उन्होंने आशा व्यक्त की कि म्यांमार में एक्ज़िम बैंक की उपस्थिति से भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा म्यांमार के विकास प्रयासों में योगदान मिलेगा. उन्होंने क्षेत्र के व्यापार तथा उद्योग निकायों से अपील की कि वे एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तपोषण तथा सहायता सेवाओं का लाभ उठायें. भारत तथा म्यांमार के बीच ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास सहयोग द्विपक्षीय संबंधों की धुरी रही है और भारत ने क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास के अलावा बुनियादी तथा गैर-बुनियादी दोनों क्षेत्रों में म्यांमार में कई विकासपरक परियोजनाओं के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की है.

भारतीय सिरैमिक उद्योग : चुनौतियां एवं रणनीतियां

भारत में सिरैमिक उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है और प्रकार, आकार तथा मानक में व्यापक अंतर के साथ बड़े तथा छोटे दोनों स्तरों पर मौजूद है. यद्यपि सिरैमिक निर्माता इकाइयां भारत भर में फैली हैं, अधिकांश इकाइयां मोरबी, सुरेंद्रनगर तथा खुरजा में संकेंद्रित हैं. तथापि गुणवत्तापूर्ण सिरैमिक माल के उत्पादन के लिए सिर्फ कुछ इकाइयों के पास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी और निर्माण सुविधाएं हैं.

सिरैमिक उत्पादों (एचएस कोड 69) का विश्व निर्यात 2011 में 43.8 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य का था. चीन सिरैमिक्स के विश्व व्यापार में 32 प्रतिशत हिस्से के साथ सिरैमिक उत्पादों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक था. 2011 में 0.36 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य के निर्यात के साथ भारत सिरैमिक के वैश्विक निर्यात में सिर्फ 0.8 प्रतिशत हिस्से के साथ 22 वां सबसे बड़ा निर्यातक था.

आयात के मामले में भारत 0.77 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य के सिरैमिक उत्पादों के आयात के साथ 11 वें स्थान पर रहा और इस प्रकार 2011 में विश्व आयात में इसका 2 प्रतिशत हिस्सा रहा **(चार्ट 1)**. सिरैमिक टाइल्स भारत से प्रमुख निर्यात मद थी जो 2011 में 92 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य का था. आयात के मामले में भी, सिरैमिक टाइल्स 256 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की थीं जिनका विश्व आयात में 1.8 प्रतिशत हिस्सा रहा. जबकि भारत सभी उप-खंडों में निवल आयातक है, निर्यात तथा आयात में अंतर सिरैमिक टाइलों तथा टेबलवेयर उत्पादों में अधिक महत्वपूर्ण रहा.

चुनौतियां

सिरैमिक उत्पाद, विशेषकर टाइल्स तथा सैनिटरीवेयर थोक मदें हैं और इस प्रकार परिवहन लागत ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते बहुत अधिक है. चूंकि उत्पादन केवल कुछ केन्दों में संकेंद्रित है, परिवहन की उच्च लागत से अंतिम लागत बढ़ जाती है अतः इसके विपरीत, आयातित सिरैमिक उत्पाद (मान लें चीन से) समुद्री मार्ग से देश में पहुंचते हैं जो लागत किफायती हैं.

उद्योग स्त्रोतों के अनुसार, उद्योग में एक प्रतिलोमित शुल्क संरचना है. उदाहरण के लिए, सिरैमिक रोलर, कलर, फ्रिट तथा बोरिक ऐसिड कच्चे माल हैं जिनका

चार्ट : भारत का सिरैमिक उत्पाद व्यापार

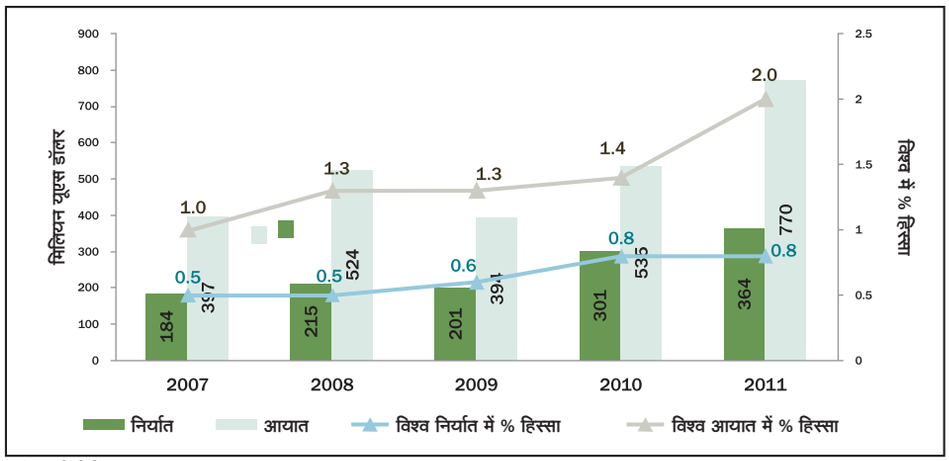

स्त्रोत : पीसीटीएएस

सिरैमिक टाइल्स के उत्पादन में व्यापक रुप से इस्तेमाल किया जाता है, इन पर 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक सीमाशुल्क लगाया जाता है, तथापि, जब सिरैमिक टाइलों के आयात की बात आती है तो चीनी टाइलों पर बैंकाक करार के अंतर्गत 4.3 प्रतिशत की अधिमान्य दर पर मूल सीमा शुल्क लगता है. इस प्रकार, सिरैमिक टाईलों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल का आयात करने वाले देशी निर्माताओं को चीन से तैयार टाइल्स आयात करने वाले आयातकों की तुलना में उच्च सीमा शुल्क अदा करना पड़ता है. यह प्रतिलोमित शुल्क संरचना ऐसे व्यापारी को अनुचित लाभ प्रदान करती है जो चीन से टाइलों (तैयार उत्पाद) का सीधे आयात करता है. इससे स्थानीय उत्पादकों की हानि होती है और इस प्रकार क्षेत्र में नये निवेशों को हतोत्साहित किया जाता है.

भारतीय कंपनियां क्षमता नहीं बढ़ा रही हैं जिसका मुख्य कारण उद्योग के भीतर अनौपचारिक समेकन है. बड़े उत्पादक एसएमई इकाइयों से उत्पादन की आउटसोर्सिंग कर रहे हैं. उद्योग विश्लेषकों का मत है कि इस अनौपचारिक समेकन से बड़े उत्पादकों द्वारा परिचालनों के अधिग्रहण और बाद में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अतरिक्त निवेश करने की संभावना को बल मिलता है.

रणनीतियां

- अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास और समुद्री परिवहन का भरपूर उपयोग किये बिना अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में भारतीय सिरैमिक उद्योग की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना कठिन होगा.

- सरकार को तैयार माल पर लगाये जा रहे सीमा शुल्क की तुलना में कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क कम करने पर विचार करना चाहिए ताकि देशी क्षमताओं के विस्तार को प्रोत्साहित किया जा सके और समान अवसर क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके. वैकल्पिक रुप से, सिरैमिक टाइल्स को बैंकाक करार से हटा दिया जाना चाहिए और अन्य देशों की तरह 10 प्रतिशत की सामान्य टैरिफ दर लगायी जानी चाहिए.

- सिरैमिक टाइल्स उद्योग, जिसमें असंगठित इकाइयों का प्रभुत्व हैं, में न्यून प्रौद्योगिकी स्तर है जो उभरते वैश्विक बाजार में बाधा के रुप में कार्य करता है. अतएव भारत में मझौले उद्यमों के लिए पूंजी निवेश की उच्चतम सीमा (वर्तमान में 2 मिलियन यूएस डॉलर) बढ़ाकर कम से कम 10 से 12 मिलियन यूएस डॉलर की जानी चाहिए. मझौले उद्यमों के लिए निवेश की उच्चतम सीमा में वृद्धि से सिरैमिक उद्योग में भी प्रौद्योगिकी व गुणवत्ता उन्नयन और निर्यात उन्मुखता के लिए उच्च निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा.

- चीनी टाइलों पर एंटी-डंपिंग शुल्क जून 2013 को समाप्त हो गया है, सरकार को यथाशीघ्र इसके विस्तार के लिए अधिसूचना जारी करनी चाहिए क्योंकि यदि यह बंद हो जाता है तो इससे बड़े पैमाने पर चीनी टाइलों की डंपिंग बढ़ेगी.

पूंजीगत माल क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक महत्व रखता है. समग्र आर्थिक वृद्धि पर इसका प्रवर्धक प्रभाव है क्योंकि यह विनिर्माण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निविष्टियां अर्थात् मशीनरी एवं उपकरण प्रदानकर प्रयोक्ता उद्योगों के व्यापक आधार के लिए विकास सुगम बनाता है.

2010-11 के दौरान पूंजीगत माल उद्योग ने 2009-10 के दौरान लगभग 1 प्रतिशत की सपाट वृद्धि दर की तुलना में 15 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की. तथापि, पूंजीगत माल उद्योग के आउटपुट में 2011-12 से गिरावट आ रही है और यह वर्ष के दौरान (-) 4.1 प्रतिशत और इसके बाद 2012-13 में भी (-) 6.1 प्रतिशत रहा.

वर्ष 2012-13 में आयात 43.4 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य का रहा जो 15.6 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात का तिगुना है. व्यापार घाटा पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल उपकरण तथा मशीनरी जैसे कुछ खंडों ने व्यापार घाटे में 20 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया है.

वैश्विक रूप से, 2011 के दौरान पूंजीगत माल का सबसे बड़ा निर्यातक कुल विश्व निर्यात में 18 प्रतिशत हिस्से के साथ चीन रहा. उसके बाद जर्मनी, यूएसए, जापान, इटली तथा हांगकांग का स्थान रहा. भारत पूंजीगत माल के कुल विश्व निर्यात में 0.6 प्रतिशत हिस्से के साथ 29 वें पायदान पर रहा. जहां तक आयात का संबंध है, भारत कुल विश्व आयात में 2 प्रतिशत हिस्से साथ 16 वें स्थान पर रहा.

प्रदर्श : सामान्य आईआईपी सूचकांक, पूंजीगत माल सूचकांक तथा पूंजीगत माल के उप-खंडों में वृद्धि

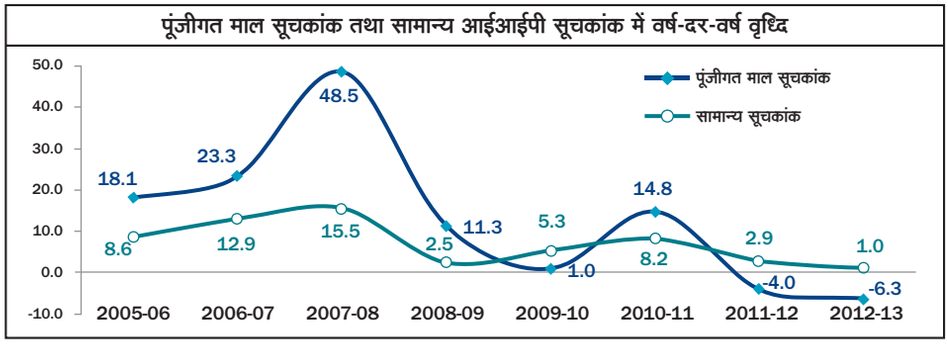

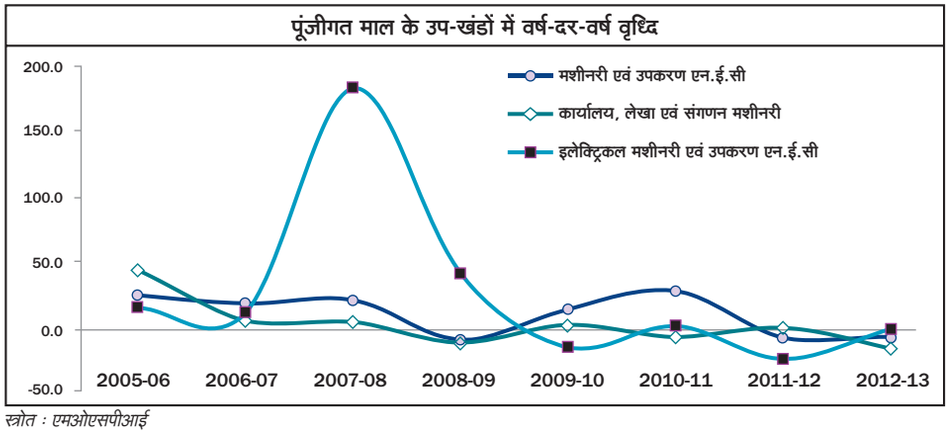

स्रोत : एमओएसपीआई

हालांकि देश में पूंजीगत माल की मांग निरंतर बढ़ रही है किन्तु देशी पूंजीगत माल निर्माता मांग पूरी करने में असमर्थ रहे हैं जिसके चलते विभिन्न बाजार खंडों में आयात पर निर्भरता बढ़ी है. यह देश में पूंजीगत माल क्षेत्र में भारी व्यापार घाटे से परिलक्षित होता है. बढ़ते आयात और देशी अर्थव्यवस्था में निम्न क्षमता निर्माण के कुछ कारणों में आयात के पक्ष में प्रतिकूल शुल्क संरचना और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीतियां शामिल हैं. पूंजीगत माल के उत्पादन के लिए प्रमुख निविष्टियों पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक सीमा-शुल्क लगता है. इसके अलावा, शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना (उत्पादन-पूर्व, उत्पादन तथा उत्पादन-पश्चात् के लिए) शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है. ईसीबी निधियों और देशी निधियों के बीच लागत अंतर (आर्बीट्रेज) लगभग 1-2 प्रतिशत आता है. ऐसी नीतियों से देशी पूंजीगत माल उद्योग अप्रतिस्पर्धी तथा अलाभप्रद स्थिति में हो जाते हैं.

पूंजीगत माल क्षेत्र को उसकी अधिकांश मांग विनिर्माण क्षेत्र से प्राप्त होती है. इस क्षेत्र का प्रदर्शन पिछले दो वर्षों के दौरान मामूली रहा है. इस क्षेत्र के अधिकांश खंडों ने व्यापार घाटा दर्ज किया है. इसके अलावा, भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा अन्य समकक्षी देशों की तुलना में अब भी बहुत कम है. विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से को जीडीपी के 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के भारत सरकार के फोकस तथा विज़न को देखते हुए आगे चलकर इसमें महत्वपूर्ण उछाल आ सकता है.

आर एंड डी तथा नवोन्मेष में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, क्लस्टर विकास दृष्टिकोण, एसएमई क्षेत्र के लिए निवेश की उच्चतम सीमा का पुनर्निर्धारण और हाई-टेक पूंजीगत माल क्षेत्र में संकेंद्रित निवेश जैसे चुनिंदा रणनीतिपरक कदम पूंजीगत माल क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को बढ़ावा देने में काफी सहायक हो सकते हैं.

समग्र रूप में, भारत में पूंजीगत माल क्षेत्र के लिए भावी संभावनाएं काफी उज्ज्वल हैं, विशेषकर मध्यम तथा दीर्घावधि में. 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए पूंजीगत माल तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र पर कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार, पूंजीगत माल तथा इंजीनियरिंग माल का उत्पादन 2011-12 में 312,557 करोड़ रूपये के स्तर से बढ़कर 2016-17 तक 681,000 करोड़ रूपये की सीमा पार कर जाने का अनुमान है.

भारत - म्यांमार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए रोडमैप

म्यांमार की अर्थव्यवस्था के खोल दिये जाने से द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश के लिए कई अवसर उभरे हैं । भारत तथा म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार में महत्वपूर्ण वृध्दि हुई और यह 2001 के 408 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2012 में 1,873 मिलियन यूएस डॉलर हो गया । 2012 में म्यांमार के वैश्विक निर्यात में भारत का 15 प्रतिशत हिस्सा रहा और इसका दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा । तथापि, म्यांमार के आयात भागीदार देश के रुप में भारत का म्यांमार के वैश्विक आयात में 3 प्रतिशत का सामान्य हिस्सा रहा तथा यह सातवाँ सबसे बड़ा आयात स्त्रोत रहा । भारत म्यांमार के साथ सामान्यतः व्यापार घाटा रखता है जो 2001 में 293 मिलियन यूएस डॉलर से बढकर 2009 में लगभग 1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया और 2012 में 819 मिलियन यूएस डॉलर रहा जो म्यांमार को भारत के निर्यात की तुलना में म्यांमार से भारत के आयात की भारी मांग दर्शाता है **(चार्ट 1)** । म्यांमार से भारत की भौगोलिक निकटता और म्यांमार की अधिकांश अग्रणी आयात मदों मे निर्यात क्षमता के बावजूद म्यांमार के आयात में भारत का हिस्सा चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया, जापान तथा मलेशिया सहित एशिया में अन्य भागीदार देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए संभाव्य क्षेत्र

म्यांमार के आयात की प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने म्यांमार की प्रमुख आयात श्रेणियों मे सिर्फ फार्मास्युटिकल उत्पादों, इत्र तथा सौन्दर्य प्रसाधन, रबड़, लौह एवं इस्पात वस्तुओं, कपास, तथा लौह एवं इस्पात के आयात में एक सम्मानित हिस्सा हासिल किया है। म्यांमार की अन्य प्रमुख आयात मदो में भारत का हिस्सा मामूली बना हुआ है ।

भारत की वैश्विक निर्यात क्षमता और साथ ही म्यांमार में बढती मांग के अनुरुप, म्यांमार को भारत की निर्यात की संभाव्य मदों में परिवहन वाहन मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लास्टिक तथा वस्तुएं, ऑप्टिकल, तकनीकी तथा डॉक्टरी उपकरण, पेपर तथा पेपरबोर्ड, ऑर्गेनिक रसायन, फर्नीचर तथा फुटवेअर उत्पाद आदि हो सकती हैं ।

म्यांमार में भारतीय निवेश और निवेश अवसर

म्यांमार में विदेशी निवेश की दृष्टि से भारत 1996 से 2013 के दौरान 192 मिलियन यूएस डॉलर के संचयी अनुमोदित निवेश के साथ 13 वें स्थान पर है। यह चीन, थाईलैंड तथा हांगकांग से पीछे है जिनका एक साथ मिलाकर देश में कुल निवेश में 73 प्रतिशत हिस्सा है ।

म्यांमार के हालिया सुधारों ने मुख्यतः इसकी रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता की बदौलत विभिन्न प्रकार के आर्थिक अवसर खोले हैं । भारी निवेश अवसर संभाव्यता वाले चुनिंदा क्षेत्रों में दूर-संचार, वित्तीय सेवाएं, बिजली उत्पादन, विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्रा एवं पर्यटन, कृषि एवं मत्स्यपालन, ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधन, उपभोक्ता उद्योग तथा प्रौद्योगिकी विकास शामिल हैं । म्यांमार सरकार ने नवंबर 2012 में एक नया विदेशी निवेश कानून अपनाया है जो निवेशकों को प्रोत्साहन तथा लाभ प्रदान कर अनुकूल निवेश वातावरण उत्पन्न करता है ।

चार्ट : म्यांमार के साथ भारत के व्यापार की प्रवृत्तियां, 2001 से 2012 (मिलियन यूएस डॉलर)

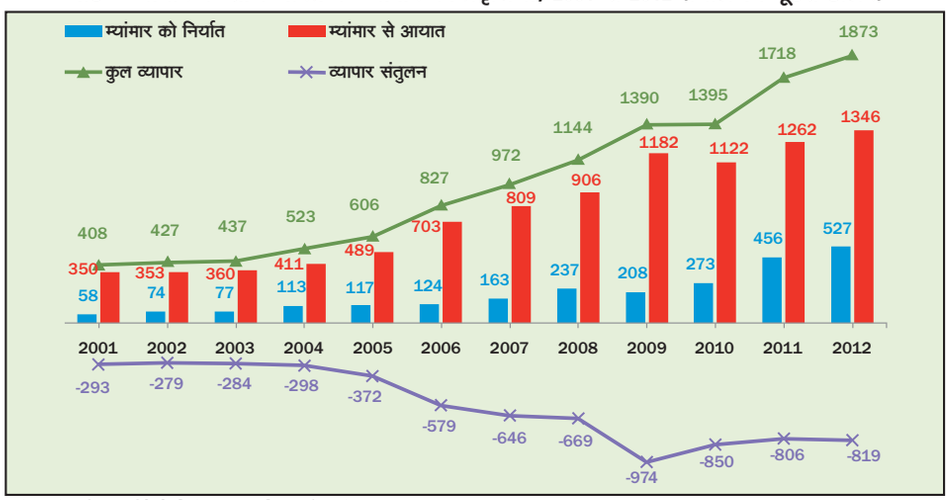

स्त्रोत : ट्रेड मैप, आईटीसी जिनेवा तथा एक्ज़िम बैंक शोध

म्यांमार में एक्ज़िम बैंक

म्यांमार में भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम भारत) ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए 247.4 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 7 ऋण व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान की हैं । जिनमें शामिल हैं - रलवे प्रणाली, कारखानों तथा रेलवे पटरीयों का उन्नयन तथा रखरखाव. ओएफसी लिंक की स्थापना, ऑटोमोबाइल असेम्बली / विनिर्माण संयंत्र, ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं, रिफाइनरी परियोजनाएं तथा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उन्नयन । म्यांमार को कुल 500 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की ऋण व्यवस्थाओं के लिए एक सहमति ज्ञापन पर भी मई 2012 में हस्ताक्षर किये गये ।

एक्ज़िम बैंक म्यांमार को परियोजना निर्यात के लिए मध्यावधि तथा दीर्घावधि क्रेता-ऋण भी प्रदान करता है। एक्ज़िम बैंक संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों के जरिए म्यांमार में निवेश करनेवाली भारतीय कंपनियों की भी मीयादी तथा कार्यशील पूंजी वित्त के जारिए सहायता प्रदान करता है ।

म्यांमार के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक्ज़िम बैंक ने हाल ही में यांगोन में अपना प्रतिनिधि कार्यालय भी खोला है ।

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं
जुलाई-सितंबर 2013

भारतीय एक्ज़िम बैंक ने गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग तथा ब्रांड निर्माण से संबंधित एक कार्यशाला के आयोजन में झारखंड सरकार के एक उपक्रम (झारक्राफ्ट) की सहायता की ताकि उनके उत्पादों को व्यापक स्वीकृति मिल सके. झारक्राफ्ट की उत्पाद श्रृंखला में धोकरा मेटल कास्टिंग, वुड क्राफ्ट्स, लाख की चूड़ियां तथा आभूषण, टेराकोट्टा हैंडीक्राफ्ट, मधुबनी, सोहराई तथा खोवर पेंटिंग्स, चमड़े के उत्पाद तथा सिल्क के सिले-सिलाये परिधान शामिल हैं.

बैंक अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने में भी उनकी मदद कर रहा है. हाल ही में, उनके बांस आधारित होम फर्निशिंग तथा सजावटी उत्पाद वैश्विक रिटेल श्रृंखला में पेश किये गये. बैंक झारक्राफ्ट से कॉरपोरेट गिफ्ट भी नियमित रूप से खरीदता है जिससे उसकी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता बढ़ती है.

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क :
सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात आयात बैंक
मुंबई
फोन : (022) 22172829
ई-मेल : deepali@eximbankindia.in

एक्ज़िमिअस केन्द्र के कार्यकलाप
जुलाई-सितंबर 2013

एक्ज़िमिअस केन्द्र ने भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) के सहयोग से 13 जून 2013 को 'यूएसए के साथ कारोबार - इलेक्ट्रिक उपकरण एवं इंजीनियरिंग सामान की संभाव्यता' विषय पर एक-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया.

एक्ज़िमिअस केन्द्र और विस्वेस्वरैया व्यापार संवर्धन परिषद (वीटीपीसी) ने धारवाड़ - हुबली तथा बेंगलोर में जून - अगस्त 2013 के दौरान कई निर्यात प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये.

नए यूरोपीय रसायन विनियम के अंतर्गत रसायनों का रजिस्ट्रेशन, मूल्यांकन, प्राधिकरण तथा प्रतिबंध (आरईएसीएच) विनियम को कठोर लक्ष्यों और उल्लंघन पर भारी दंड के प्रावधानों के साथ लागू किया गया है. अतएव, एक्ज़िमिअस केन्द्र ने भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) के साथ संयुक्त रूप से 26 जुलाई 2013 को 'आरईएसीएच के बारे में जानकारी' पर एक अर्ध्द-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया.

एक्ज़िमिअस केन्द्र ने पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के सहयोग से जालंधर, पंजाब में 28 जून 2013 को 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का समूह वित्तपोषण' विषय पर एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया.

एक्ज़िमिअस केन्द्र ने भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) के सहयोग से सेनवैट क्रेडिट, निर्यात दस्तावेज, रिबेट / रिफंड का दावा करना, निर्यात के लिए विभिन्न बांड तथा वचनपत्र, सेवा कर रिफंड, निर्यात-आयात सेवा से संबंधित विभिन्न पहलुओं से निर्यातकों को अवगत कराने के उद्देश्य से 30 जुलाई 2013 को 'केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सेवा कर' पर एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया.

एक्ज़िमिअस केन्द्र ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नै में सेवा पर कई चर्चापरक सत्रों का आयोजन किया. डॉ एचएसी प्रसाद, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार तथा अवर सचिव, वित्त मंत्रालय ने इन बैठकों की अध्यक्षता की.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के समान विधि प्रणाली 600 (यूसीपी 600) पर विभिन्न भुगतान शर्तों के बारे में निर्यातकों को जानकारी देने के उद्देश्य से एक्ज़िमिअस केन्द्र ने एफआईईओ के सहयोग से बेंगलोर में 22 अगस्त 2013 को 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान और यूसीपी 600' पर एक-दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया.

व्यापार से संबंधित विधियों एवं प्रक्रियाओं के विभिन्न सिध्दांतों तथा संकल्पनाओं, नीतियों तथा दस्तावेजीकरण से पूर्वोत्तर राज्यों के निर्यातकों को अवगत कराने के उद्देश्य से नागालैंड सरकार तथा एफआईईओ के सहयोग से दिमापुर, नागालैंड में 22 अगस्त 2013 को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया.

एक्ज़िमिअस केन्द्र और अर्जेंटिना वाणिज्यदूतावास ने कोलकाता में 11 सितंबर 2013 को 'अर्जेंटिना के साथ कारोबार' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया. माननीय टॉमस फेरारी, महावाणिज्यदूत, अर्जेंटिना महा वाणिज्यदूतावास, मुंबई ने सहभागियों को संबोधित किया.

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क :
श्री टी. वी. राव
सलाहकार - एक्ज़िमिअस केन्द्र
भारतीय निर्यात आयात बैंक
बेंगलोर
फोन : (080) 25589106
ई-मेल : eximius@eximbankindia.in

पुस्तक समीक्षा

'ग्लोबल रीबैलेंसिंग : ए रोडमैप फॉर इकोनॉमिक रिकवरी' - आईएमएफ

संकट के पांच वर्षों बाद, समूह बीस (जी 20) की उनत तथा उबरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने अपने प्रमुख आंतरिक तथा बाह्य असंतुलनों को कम करने में कुछ प्रगति दिखाई है. तथापि, स्थायी तथा संतुलित वैश्विक वृध्दि के लिए अधिक समन्वित नीतिगत कार्रवाई आवश्यक है.

यह प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसंधान विभाग द्वारा जी-20 के लिए तैयार की गई रिपोर्टों के सेट और म्यूच्युअल असेसमेंट प्रोसेस (मैप) पर आधारित है.

यह प्रकाशन जी-20 दिशानिर्देशों के आधार पर अपेक्षाकृत भारी मध्यावधि असंतुलन रखने के रूप में पहचान की गई नौ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं - चीन, यूरो क्षेत्र, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जपान, स्पेन, यूके तथा संयुक्त राज्य के लिए सामान्य प्रवृत्तियों तथा अलग-अलग देशों की स्थितियों का मूल्यांकन करता है. प्रमुख असंतुलनों का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त संकेतकों में लोक ऋण तथा राजकोषीय घाटा; निजी बचत तथा निजी ऋण; और व्यापार वित्त, निवल निवेश आय प्रवाह तथा अंतरण सहित बाह्य स्थितियां शामिल हैं. यह वैश्विक आर्थिक वृध्दि को पुनः पटरी पर लाने के लिए सुदृढ संयुक्त नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है.

रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि दो विस्तृत आयामों के साथ-साथ नीतिगत समायोजन की आवश्यकता है. पहला, और अधिक आंतरिक पुनर्संतुलन की आवश्यकता है. दूसरा, प्रमुख अधिशेष तथा घाटे वाली अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप नीतियां तैयार करते हुए और अधिक बाह्य पुनर्संतुलन की आवश्यकता है. अधिशेष वाले देशों को आंतरिक मांग को टिकाऊ रूप से मजबूत बनाने (जर्मनी) या अपनी संरचना को संशोधित करने (चीन) के लिए संरचनात्मक सुधार करना होगा. घाटे वाली अर्थव्यवस्थाओं में, नीति निर्माताओं को बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए तैयार किये गये संरचनात्मक सुधारों पर फोकस करना चाहिए. इनमें उत्पाद बाजार सुधार (स्पेन, फ्रांस), सेवा क्षेत्र उदारीकरण (फ्रांस, जर्मनी), कामगार कौशल और बैंकिंग क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना (यूके) और निर्यात को मजबूत बनाने के लिए आपूर्ति बाधाओं को हटाना (भारत) शामिल हैं.

14 देशों का सूक्ष्मावलोकन

मोजाम्बिक

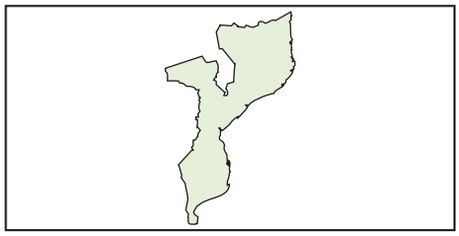

मोजाम्बिक 30 वर्षों के संघर्ष के बाद अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने और वृध्दि को पुनः पटरी पर लाने के लिए एफडीआई पर अत्यधिक निर्भर रहा है. कोयला और टिटैनियम राजस्व के बढ़ते स्त्रोत हैं और प्राकृतिक संसाधन आधारित बृहत् परियोजनाएं मोजाम्बिक की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुई हैं. देश विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और विदेशी निवेशक मोजाम्बिक के अप्रयुक्त तेल एवं गैस भंडार में रूचि दिखा रहे हैं. हाल ही में भारत सरकार ने मोजाम्बिक में सौर पैनलों की पहली फैक्टरी स्थापित करने के लिए नेशनल एनर्जी फंड के साथ एक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें 13 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश शामिल है. फैक्टरी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरण ऊर्जा के प्रयोग को विस्तारित करना है.

कज़ाखस्तान

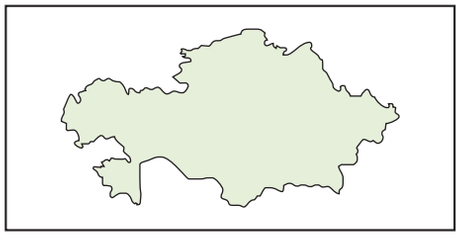

कज़ाखस्तान विशाल जीवाश्म ईंधन भंडार और यूरेनियम, तांबा तथा जिंक जैसी अन्य धातुओं की प्रचुर आपूर्ति से सम्पन्न है. हालांकि कज़ाखस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी वैश्विक वित्तीय संकट का गहरा प्रभाव पड़ा है किन्तु यह उठाये गये विवेकपूर्ण सरकारी उपायों से उबर गया है. आईएमएफ अनुमानों के अनुसार, जीडीपी में 2011 में 7.5 प्रतिशत और 2012 में 5.5 प्रतिशत की वृध्दि हुई. औद्योगिक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बढ़े निवेश और कशागन ऑयल फील्ड में विकास के चलते 2014-18 की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में 6-7 प्रतिशत की वृध्दि होने का अनुमान है. निष्कर्षण उद्योग कज़ाखस्तान की वृध्दि का संवाहक रहा है और इसके संवाहक बने रहने की संभावना है, हालांकि देश परिवहन, औषधि, दूर-संचार, पेट्रोकेमिकल तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से विविधीकरण रणनीतियों को आक्रामक रूप से बढ़ाव दे रहा है.

ब्राजील

ब्राजील की अर्थव्यवस्था विशाल तथा सुविकसित कृषि, खनन, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों से सम्पन्न है. 2007 तथा 2008 में जोरदार वृध्दि के बाद आसन्न वैश्विक वित्तीय संकट से 2008 में ब्राजील भी प्रभावित हुआ. तथापि, यह देश संकट से उबरने में पहले उभरते बाजारों में से एक था. वर्ष 2010 में, उपभोक्ता तथा निवेशक विश्वास पुनः बहाल हुआ और जीडीपी वृध्दि 7.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गयी जो पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक वृध्दि दर थी. बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए प्राधिकारियों ने अर्थव्यवस्था को सुस्त करने के लिए उपाय किये. इन कार्यवाहियों तथा बिगड़ती अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के चलते वृध्दि दर 2011 में घटकर 2.7 प्रतिशत और 2012 में 1.5 प्रतिशत हो गई. विगत कई वर्षों के दौरान भारी मात्रा में पूंजी अंतर्वाह ने मुद्रा की मूल्यवृध्दि में योगदान दिया है जिससे ब्राजीलियाई विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है और सरकार को विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा है तथा कुछ विदेशी पूंजी अंतर्वाहों पर कर लगाना पड़ा है.

श्रीलंका

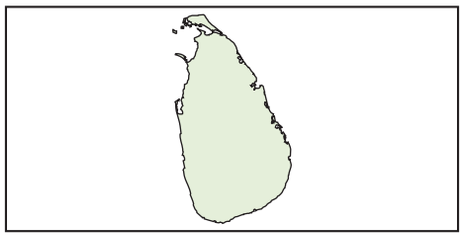

श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था 2009 के मध्य में गृह-संघर्ष की समाप्ति के बाद उछाल पर है. वर्ष 2012 में यह अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी जिसमें आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार 6.7 प्रतिशत की वृध्दि हुई है. भविष्य में प्रति वर्ष 8 प्रतिशत से अधिक की वृध्दि दर प्राप्त करना और उसके द्वारा वर्तमान प्रति व्यक्ति आय को 2016 तक दुगुना करके लगभग 4000 यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंचाना इसका लक्ष्य है. देश की आर्थिक वृध्दि की मजबूत स्थिति का लाभ उठाने के लिए, सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ श्रीलंका इस महाद्वीप के वित्तीय बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार के विकास तथा विनियमन की दिशा में प्रमुख कदम उठा रहा है. इसने वर्ष 2013 के लिए 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई लक्ष्य रखा गया है. विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियम में हालिया ढील एफडीआई अंतर्वाह प्रेरित करने की दिशा में एक कदम है. देश ने पोर्ट, पर्यटन तथा वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश अवसरों की तलाश करने के लिए भारतीय व्यावसायिक समुदाय को आमंत्रित किया है.

इंडोनेशिया

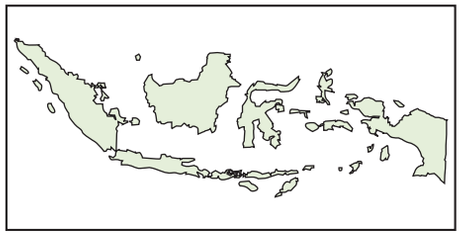

इंडोनेशिया ने 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद पुनरूत्थान किया है और विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. निवेशक विशाल उपभोक्ता आधार, प्राकृतिक संसाधन और राजनीतिक स्थिरता से आकर्षित हैं. हाल के वर्षों में इंडोनेशिया की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है. इससे जीडीपी - ऋण अनुपात में गिरावट आयी है जो 2008 के लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 2012 में 23 प्रतिशत अनुमानित है. तथापि, इंडोनेशिया का पण्य व्यापार अधिशेष कमजोर बाह्य मांग तथा आयात की जोरदार मांग के कारण 2011 के 33.8 बिलियन यूएस डॉलर से तेजी से घटकर 2012 में 8.7 बिलियन यूएस डॉलर रह गया. व्यापार अधिशेष में गिरावट का अर्थ यह है कि 14 वर्षों तक के चालू खाता अधिशेष के बाद इंडोनेशिया ने 2012 में जीडीपी के 2.7 प्रतिशत के समतुल्य घाटा दर्ज किया. मुद्रा भी 2012 के दौरान यूएस डॉलर के मुकाबले मूल्य की दृष्टि से लगभग 6.6 प्रतिशत गिरावट के साथ कमजोर रही.

सिंगापुर डॉलर

सिंगापुर डॉलर (एसजीडी) अस्थिर दर व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधित है जहां विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा बाजार में मांग तथा आपूर्ति द्वारा किया जाता है. सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकारी (एमएएस) सिंगापुर की प्रमुख व्यापारिक भागीदारी मुद्राओं के मुकाबले सिंगापुर डॉलर का प्रबंध करता है और इसे मोटे तौर पर अप्रकटित लक्ष्य सीमा के अंदर बनाये रखता है.

सिंगापुर डॉलर अगस्त में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1.2860 के स्तर तक कमजोर हुआ जिसका आंशिक कारण घाटे से प्रभावित उभरती अर्थव्यवस्थाओं में घटी हुई दर पर बिक्री के संक्रामक रोग का डर था. सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के बावजूद, अन्य उभरती बाजार मुद्राओं की कमजोरी सिंगापुर डॉलर के लिए नकारात्मक साबित होगी. डॉलर के मुकाबले सिंगापुर डॉलर का प्रदर्शन बेहतर प्रदर्शनवाली उत्तर-पूर्व एशियाई मुद्राओं और कमजोर प्रदर्शनवाली दक्षिण-पूर्व एशियाई मुद्राओं के बीच सैंडविच की तरह रहा जिसमें अगस्त में 0.31 प्रतिशत की हानि हुई. दीर्घावधि में, सकारात्मक आर्थिक स्थितियां अब भी सिंगापुर डॉलर के लिए सहायता प्रदान करेंगी. यह सतत् चालू खाता अधिशेष पर आधारित है जो शेष क्षेत्र से विपरीत, माल शेष में वृध्दि के चलते पहली तिमाही के 14.1 बिलियन एसजीडी से बढ़कर दूसरी तिमाही में 18.0 एसजीडी हो गया. 2013 की दूसरी छमाही में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भी सिंगापुर के देशी तेल निर्यात, जिसका कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है, का मूल्य बढ़ेगा.

चीन पीएमआई तथा यूएस आईएसएम में वृध्दि के मद्देनज़र एसजीडी संकेत मिश्रित हैं जबकि अगस्त में सिंगापुर के स्थानीय पीएमआई में गिरावट आयी. बाजार को उम्मीद है कि एमएएस अक्तूबर में फॉरेक्स नीति को अपरिवर्तित रखेगा जिसके परिणामस्वरूप एसजीडी की नाममात्र प्रभावी विनिमय दर निकट समय में मजबूत रहेगी. यथा 30 सितंबर 2013 को यूएस डॉलर के मुकाबले एसजीडी 1.2557 पर उध्दृत हो रहा था.

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (एयूडी) विदेशी मुद्रा लेन-देनों में 6 प्रतिशत से अधिक हिस्से के साथ वर्तमान में वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में सर्वाधिक क्रय-विक्रय वाली छठी मुद्रा (यूएस डॉलर, यूरो, येन, पौंड स्टर्लिंग तथा स्विस फ्रैंक से पीछे) है. चूंकि ऑस्ट्रेलिया के निर्यात में पण्यों का भारी अनुपात होता है, अतः पण्यों की कीमतों और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के बीच घनिष्ठ संबंध है. जब पण्यों की वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य बढ़ता है और जब कीमतें घटती हैं तो मूल्य घटता है. फलस्वरूप, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को कभी-कभी 'पण्य मुद्रा' के रूप में भी उल्लिखित किया जाता है.

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूएस फेड के परिसंपत्ति क्रय कार्यक्रम में समयपूर्व कटौती के संबंध में अटकलबाजी के बीच कमजोर हुआ है. अगस्त में दरों में कटौती (25 आधार बिंदु कम करके 2.5 प्रतिशत) और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मूल्य में और कमी के बारे में आरबीए की टिप्पणी का भी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर प्रभाव पड़ा. ट्रेजरी प्रतिलाभ में वृध्दि के कारण यूएस ट्रेजरी की तुलना में ऑस्ट्रेलियाई बांडों के घटते ब्याज दर अंतर के चलते भी मुद्रा दबाव में रही है. आगे चलकर, मंद देशी वृध्दि और फेड द्वारा मात्रात्मक नरमी को कम करने की अटकलबाज़ी के चलते ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के दबाव में रहने की संभावना है. पूंजी प्रवाह में और गिरावट की संभावना के चलते ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में कुछ और गिरावट आ सकती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खनन क्षेत्र अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है जबकि विनिर्माण क्षेत्र मंद है. तथापि, इस वर्ष नीतिगत मोर्चे पर किसी अतिरिक्त कार्रवाई की संभावना न होने और साथ ही प्रत्याशित से बेहतर चीनी डाटा प्रिंट से कुछ समर्थन मिल सकता है और हानि को सीमित रखा जा सकता है. यथा 30 सितंबर 2013 को यूएस डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1.0728 पर उध्दृत हो रहा था.

स्विस फ्रैंक

स्विस फ्रैंक (सीएचएफ) स्विट्जरलैंड की सरकारी मुद्रा है. इसे स्विट्जरलैंड के केन्द्रीय बैंक 'स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी)' द्वारा जारी किया जाता है. स्विस फ्रैंक यूरोप में बची हुई एकमात्र मुद्रा है जिसके नाम में फ्रैंक जुड़ा है.

स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक (एसएनबी) को विनिमय दर की उच्चतम सीमा अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली स्थितियां अब आंशिक रूप से धूमिल पड़ गयी हैं. ईएमयू सॉवरिन स्प्रेड तेजी से कम हुआ है. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अब नकारात्मक नहीं रह गयी है और अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है. बाजार को उम्मीद है कि एसएनबी आगामी कुछ समय तक फॉरेक्स की मूल्यवृध्दि पर हस्तक्षेप करता रहेगा. पहला; मूल मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य, पेय, तम्बाकू तथा ऊर्जा शामिल है, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर थोड़ी कम है (जून में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर - 0.2 प्रतिशत). दूसरा; देशी मुद्रास्फीति दबाव उत्पन्न किये बिना वृध्दि होने देने के लिए अर्थव्यवस्था में भारी मंदी है. तीसरा; मजबूत स्विस फ्रैंक और कमजोर ईएम वृध्दि विशेषकर स्विट्जरलैंड के परिष्कृत उपभोक्ता माल उद्योगों के लिए गंभीर प्रतिकूल हवा प्रस्तुत करता है.

स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था देश की मुद्रा के लिए सुरक्षित-आश्रय मांग के सहारे अपेक्षाकृत ठोस आकार में है. स्विस नेशनल बैंक ने अवस्फीति तथा मंदी से बचाव करने के लिए लगभग दो वर्ष पहले इस मुद्रा की विनिमय दर 1.20 प्रति यूरो नियत की थी. ऐसी आशा है कि यदि आर्थिक वृध्दि वर्ष की दूसरी छमाही में जारी रहती है तो एसएनबी तब तक कठोर मौद्रिक नीति अपनायेगा जब तक यूरो - स्विस फ्रैंक की विनिमय दर 1.30 पर पहुंच नहीं जाती है और इसका विदेशी मुद्रा भंडार धीरे-धीरे वापस बढ़ नहीं जाता है. यदि वृध्दि और भी तेज रहती है तथा वर्ष के अंत तक स्विस पीएमआई 60 बिंदु से ऊपर रहता है तो एसएनबी विनिमय दर के 1.27 फ्रैंक प्रति यूरो पहुंचने पर फ्रैंक पर अंकुश रखने के लिए जुटाये गये विदेशी मुद्रा भंडार को पहले ही बेचना शुरू कर देगा. यथा 30 सितंबर 2013 को यूएस डॉलर के मुकाबले स्विस फ्रैंक 0.9054 पर उध्दृत हो रहा था.

16

प्रौद्योगिकी उन्मुख विनिर्माण में व्यापार संभाव्यता

यद्यपि भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा पिछले दो दसकों से लगभग 15 प्रतिशत के आस-पास घूम रहा है, वैश्विक विनिर्मित वस्तुओं में भारत का हिस्सा सिर्फ 1.8 प्रतिशत रहा. चीन से तुलना करने पर भारत विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में फिसड्डी है. चीन में विनिर्मित वस्तुओं का जीडीपी में 34 प्रतिशत और विश्व विनिर्मित वस्तुओं में 13.7 प्रतिशत हिस्सा है

विनिर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी व्यापन का अभाव इस क्षेत्र के लचर प्रदर्शन का प्रमुख कारण रहा है. हालांकि विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के प्रतिशत के रूप में भारत के उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात में 1991 से सुधार आया है लेकिन पिछले 10 वर्षों के दौरान मुख्यतः स्थिर रहा है जबकि कई उभरते देशों का हिस्सा दो अंकों में रहा : मलेशिया (43.4 प्रतिशत), चीन (25.8 प्रतिशत), कोरिया (25.7 प्रतिशत) तथा मेक्सिको (16.5 प्रतिशत). वर्तमान में, कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में और साथ ही चीन जैसी कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का कुल निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है. इसके विपरीत, भारत का हिस्सा 2011 में 7 प्रतिशत था जबकि वैश्विक रूप से 0.8 प्रतिशत था.

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय उद्योग द्वारा वर्तमान में निर्मित किये जा रहे उत्पादों में औसत प्रौद्योगिकी मूल्य योजन लगभग 8 प्रतिशत है. साथ ही, भारत में आर एंड डी में उद्योग के निवेश का हिस्सा जीडीपी का लगभग 1 प्रतिशत है, इसकी तुलना में अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह अनुसंधान एवं विकास पर सकल देशी व्यय (जीईआरडी) का लगभग तीन-चौथाई है. यह चौंकने वाली बात है कि आर एंड डी निवेश में उद्योग का हिस्सा लगभग एक-चौथाई है और शेष तीन-चौथाई सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश किया गया है और अतएव निजी क्षेत्र के नवोन्मेषण में अवसर सृजित करने की आवश्यकता है.

प्रौद्योगिकी व्यापार : परिप्रेक्ष्य

वैश्विक रूप से, प्रौद्योगिकी निर्यात में उच्च, मध्यम तथा निम्न सभी श्रेणियों में वृध्दि दर्ज हुई है. यद्यपि विश्व से उच्च प्रौद्योगिकी का निर्यात मध्यम प्रौद्योगिकी तथा निम्न प्रौद्योगिकी निर्यात से अपेक्षाकृत कम रहा है. चीन का हिस्सा 2007 से लगातार बढ़ा है जो 2011 में उच्च प्रौद्योगिकी में 20 प्रतिशत, मध्यम-प्रौद्योगिकी में 10.4 प्रतिशत और निम्न प्रौद्योगिकी में 26.4 प्रतिशत हिस्से के साथ विश्व में प्रमुख प्रौद्योगिकी निर्यातक के रूप में उभरा है.

भारत का प्रौद्योगिकी विनिर्मित निर्यात विश्व के प्रौद्योगिकी निर्यात के तुल्यकालिक पाया गया है. भारत से उच्च प्रौद्योगिकी का निर्यात 2007 से 2011 के दौरान 2.5 गुना बढ़ा है जो मजबूत संभाव्यता प्रदर्शित करते हुए सकारात्मक वृध्दि है. हालांकि भारत के उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात में औषधि निर्यात की प्रमुखता रही, इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा वैश्विक मांग के अनुरूप इस अवधि के दौरान दुगुना हो गया. भारत का उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात मुख्यतः विकसित देशों को हुआ है और अतएव अविकसित देशों में निर्यात गंतव्य स्थान विस्तारित करने की आवश्यकता है.

मध्यम प्रौद्योगिकी के भारतीय निर्यात की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए निर्यात किये जाने वाले शीर्ष 10 मध्यम प्रौद्योगिकी उत्पादों के सीएजीआर में दो अंकों की वृध्दि दर्ज हुई है. उनके हिस्से में भी 2007 के 33.2 प्रतिशत से 2011 में 41.7 प्रतिशत की जोरदार वृध्दि हुई है. उच्च प्रौद्योगिकी तथा मध्यम प्रौद्योगिकी श्रेणी के विपरीत, निम्न प्रौद्योगिकी श्रेणी में 2009 के वैश्वि वित्तीय संकट से प्रभावित हुए बिना विश्व को भारत से निर्यात में आनुक्रमिक वृध्दि दर्ज हुई है.

व्यापार बढ़ाने के लिए चुनिंदा उपाय

➢ चीन में चेंगडु और यूएसए में कोलोराडो, जिन्होंनें स्थल-रूध्द होने के बावजूद विकास किया है, की तरह उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्रों के सफल विकास मॉडलों की पुनरावृत्ति करना और अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना तथा पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में अधिक कर राजस्व उत्पन्न करना.

➢ रिजर्व बैंक निवल ब्याज मार्जिन पर नियत उच्चतम सीमा के साथ वाणिज्यिक बैंकों को रेपो दर पर उदार दे सकता है. ऐसा पुनर्वित्त बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) वित्तपोषण और साथ ही निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) वित्तपोषण की लागत से सस्ता होगा.

➢ स्थानीयकरण के लिए सार्वजनिक प्रापण और प्रौद्योगिकी अंतरण का लाभ उठाने के लिए नीतिगत उपायों को सांस्थनिक बनाना.

➢ उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण पर सरकार के विशेष जोर को देखते हुए अधिसूचित उच्च प्रौद्योगिकी क्लस्टरों और उनमें परिचालनरत इकाइयों को उधार को समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के एक हिस्से के रूप में निर्धारित किया जा सकता है. भारत को उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का एक मुख्य विनिर्माण केन्द्र बनाने पर सरकार के विशेष बल के मद्देनज़र रिजर्व बैंक को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 10 प्रतिशत पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को उधार देने के लिए उप-लक्ष्य निर्धारित करने और समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार को एएनबीसी के 45 प्रतिशत तक बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए.

➢ सरकार उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण के लिए अधिसूचित 'राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों' (एनआईएमजेड) को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का दर्जा देने पर भी विचार कर सकती है और सभी अधिसूचित उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों को शामिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों के दायरे को बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है.

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्त्रोतों / माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रामाणिक हैं । प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रामाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है ।

नोट : भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है

1 करोड़ : 10 मिलियन

1 लाख : 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005
दूरभाष : +91-22-2217 2600
फैक्स : +91-22-2218 2572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

सितंबर 2013
खंड XXVII अंक III

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ - फीड बैंक (प्रतिपुष्टि) फार्म

कृपया इसे और बेहतर बनाने में हमारी सहायता करें ।

1. आप किससे संबंधित हैं *(जो लागू हो उस पर टिक करें)*
   - ☐ सरकारी संस्था
   - ☐ गैर-सरकारी संस्था
   - ☐ कार्पोरेट
   - ☐ निर्यातक
   - ☐ शैक्षणिक संस्था
   - ☐ व्यक्तिगत
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें*.....

2. हमारे इस प्रकाशन के बारे में आपके विचार
   - ☐ समझने में आसान एवं उपयोगी
   - ☐ थोड़ा सहायक
   - ☐ व्यापक
   - ☐ बिल्कुल उपयोगी नहीं

3. आप किस क्षेत्र में रूचि रखते हैं? *(कृपया टिक करें)*
   - ☐ क्षेत्रीय/औद्योगिक परिदृश्य *कृपया उल्लेख करें*
   - ☐ देश/क्षेत्रीय परिदृश्य *कृपया उल्लेख करें*
   - ☐ व्यवसाय अवसर एवं संविदा
   - ☐ एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएँ
   - ☐ तिमाही समाचार
   - ☐ देशों का अवलोकन
   - ☐ मुद्रा की प्रवृत्तियाँ
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें*.....

4. क्या आप हमारे प्रकाशन से संतुष्ट हैं?
   - ☐ बेहद संतुष्ट
   - ☐ संतुष्ट
   - ☐ सामान्य
   - ☐ असंतुष्ट

5. क्या हमारा प्रकाशन आपके लिए उपयोगी रहा है? *(किसी एक को चुनें)*
   - ☐ इसने काफी मदद की
   - ☐ यह उपयोगी रहा
   - ☐ कह नहीं सकते
   - ☐ यह उपयोगी नहीं रहा
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें*.....

6. आपको हमारा प्रकाशन कब से मिल रहा है? *(किसी एक को चुनें)*
   - ☐ एक वर्ष से कम समय से
   - ☐ लगभग 1-3 वर्ष से
   - ☐ लगभग 3-5 वर्ष से
   - ☐ 5 वर्ष से अधिक समय से

7. आप यह प्रकाशन किस भाषा में चाहेंगे?
   - ☐ अंग्रेजी
   - ☐ हिन्दी

8. हमारे इस प्रकाशन के बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे?
   - ☐ हाँ
   - ☐ नहीं

   यदि हाँ, तो कृपया लिखें!

कृपया अपने सुझाव/फीडबैक हमें फैक्स/ई-मेल/डाक से निम्नलिखित पते पर भेजें : निगमित कार्य समूह, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ परेड, मुंबई - 400 005

फैक्स : +91-22 22182572, ई-मेल : cag@eximbankindia.in

नाम :_____

संपर्क विवरण :_____